आज का विचार

दुनिया की कोई भाषा नहीं जो पृथक व्यक्तियों के निगूढ़तम मर्म के बीच वास्तविक सेतु का काम कर सके।

दैनिक

सिटी दर्पण

आईना सच का

2

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शुक्रवार, 2 मई, 2025 वर्ष 23, अंक 110, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

इंसान की समृद्धि के लिए गीत, संगीत, कला को महत्व देना होगा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मोदी ने किया मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट-2025 (वेव्स) का उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट-2025 (वेव्स) का उद्घाटन किया और इसे सृजनात्मकता का वैश्विक उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत में सृजन करें, विश्व के लिए सृजन करें की अवधारणा को अपनाने का एकदम सही समय है। इंसान की समृद्धि इन्फोर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा।प्रधानमंत्री ने समिट में गुरु दत्त, पी. भानुमति और ऋत्विक घटक सहित भारतीय सिनेमा के पांच दिग्गजों के नाम पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किए।

उन्होंने कहा कि वेव्स केवल शब्द-संक्षेप नहीं है; यह संस्कृति, रचनात्मकता, फिल्में, संगीत, गेमिंग, कहानी कहने की शैली की एक लहर है।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक जगत का आह्वान करते हुए कहा कि भारत की हर गली में एक कहानी है।मैं हमेशा कहता हूं, यही समय है, सही समय है । यह भारत में सृजन करने और विश्व के लिए सृजन करने का सही समय है। आज जब विश्व कहानी कहने के नए-नए तरीके खोज रहा है, भारत के पास हजारों वर्षों की कहानियों का खजाना है और यह खजाना कालातीत, विचारोत्तेजक और सही मायने में वैश्विक है।

प्रधानमंत्री ने रचनात्मक जिम्मेदारी के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि 21वीं सदी की तेज-तर्रार, तकनीक-संचालित दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। यहीं पर रचनात्मक दुनिया (क्रिएटिव वर्ल्ड) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा लक्ष्य इंसानों को रोबोट में बदलना नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी के बीच अधिक संवेदनशीलता और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। इंसान की समृद्धि इन्फोर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। हजारों सालों से ये मानवीय संवेदना को जागृत रखे हुए हैं। हमें इसे और मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि यह भारत में ओरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर ये ऑरेंज इकॉनमी की तीन धुरी है। भारतीय फिल्मों की रीच अब दुनिया के कोने-कोने में पहुंच रही है। आज 100 से अधिक देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती हैं। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक भारतीय सामग्री को उपशीर्षक के साथ देख रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से फिल्म निर्माण, डिजिटल सामग्री, गेमिंग, फैशन और संगीत के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। लाइव मनोरंजन उद्योग, विशेष रूप से लाइव कॉन्सर्ट भी देश में विकास की अपार संभावनाएं रखता है। वर्तमान में वैश्विक एनीमेशन बाजार का मूल्य 430 बिलियन डॉलर से अधिक है और अगले दशक में इसके दोगुना होने का अनुमान है। यह भारत के एनीमेशन और ग्राफिक डिजाइन उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर खुद को स्थापित करने और विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है।

उन्होंने युवाओं से कहा कि आज हमारी युवा पीढ़ी को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है।वेब्स एक ऐसा मंच है जो ये काम कर सकता है। यदि हम इस जिम्मेदारी से पीछे हट गए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। आज टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान बना दिया है। इसलिए अब ग्लोबल कॉर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्लेटफार्मे हमारे क्रिएटर्स को ग्लोबल स्टोरी टेलीस्टोरर से कनेक्ट करेगा। हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा।7

नायब सैनी ने स्वास्थ्य सुविधाओं, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर दिया बल

मुख्यमंत्री ने की विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने इस वर्ष मार्च में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी।

विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जाए। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एक्स-रे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनलाइजर जैसी डायग्नोसिटक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर कम से कम एक अस्पताल को अपग्रेड करने के कार्य में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह सुसज्जित हों।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गाँवों के मौजूदा तालाबों के जीर्णोद्धार के अलावा, जिन गांवों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उनमें नए तालाबों का निर्माण किया जाए। उन्होंने रिचार्ज-वैल के निर्माण के लिए गांवों में उपयुक्त भूमि की पहचान करने के भी निर्देश दिए, ताकि अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहीत किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल भूजल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित स्थान प्रदान करने के लिए गांवों के नजदीक स्कूलों या अन्य भवनों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाए। इन पुस्तकालयों में फर्नीचर और शीर्ष प्रकाशकों की पुस्तकें शामिल की जाए, जिससे छात्रों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित होगा। इस वर्ष 15 अगस्त तक लगभग 950 ई-पुस्तकालयों का निर्माण पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ग्रामीण मिशन के अंतर्गत आदर्श गांव विकसित करने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के तहत गांवों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य भर में स्लम-एरिया के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को पानी के उपयोग को कम करने के लिए सभी बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गुरुग्राम में वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए स्थापित किए जा रहे तीन उत्कृष्टता केंद्रों में खाद्य प्रसंस्करण और मार्केट लिंकेज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11-18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना नूंह जिले में संचालित है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि छः जिलों में बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास में कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा किया जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य घर की छतों पर 2 किलोवाट तक के सौर पैनल लगाकर लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। वे जल्द ही योजना के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक गांव का दौरा करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, उप प्रधान सचिव यशपाल, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बीबीएमबी पंजाब को दरकिनार करके हरियाणा को पानी नहीं जारी कर सकता: भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नंगल डैम पहुंचे

संवाददाता

नंगल (रूपनगर)

पंजाब के पास किसी और को देने के लिए एक भी बूंद अतिरिक्त न होने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) तानाशाही ढंग से पंजाब को हुक्म चलाकर हरियाणा को पानी नहीं छोड़ सकता। आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से के आवंटित पानी से 16000 क्यूसेक पानी अधिक इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और हरियाणा ने पंजाब के पानी पर डाका डालने के लिए आपस में गठजोड़ कर लिया है और बी.बी.एम.बी. ने कानून की धज्जियां उड़ाकर हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने का फैसला कर लिया जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बी.बी.एम.बी. में पंजाब का 60 फीसदी हिस्सा है और बोर्ड का यह फैसला मनमाना, तानाशाही और गैर-लोकतांत्रिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.बी.एम.बी. को पंजाब और इसके हितों को दरकिनार करके किसी को पानी देने का कोई हक नहीं है और किसी भी सूरत में ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा, ‟जैसे एक किसान हर वक्त अपने हिस्से के पानी की रक्षा करता है, उसी तरह पंजाब और इसके पानी का रखवाला होने के नाते मैं यहां प्रबंधों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं ताकि कोई भी पंजाब के पानी की चोरी न करे।

-संबंधित खबर पेज 5 पर

भारत की पहलगाम हमले पर अमेरिका से चर्चा, जयशंकर ने मार्को से कहा-गुनहगारों को न्याय के कठघरे में लाया जाए

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

भारत की पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिका से चर्चा हुई है। भारत ने पहलगाम हमले के गुनहगारों, समर्थकों और हमले की योजना बनाने वालों को न्याय के कठघरे में लाने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।

विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज सुबह एक्स पर लिखा, "कल अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रुबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। इसके अपराधियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।" सनद रहे इस हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। निर्दोष लोगों की हत्या से लोग आहत हैं। देश में पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुनहगारों को कठोरतम दंड दिलाकर पहलगाम पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दंडात्मक उपायों की घोषणा की है। इसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। भारत की इस घोषणा से आतंकवादियों के गढ़ के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है।

भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयरस्पेस किया बंद, 23 मई तक लगाई पाबंदी

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नोटिस टू एयर मिशन (नोटम) जारी किया है।

इस नोटम के तहत भारत ने पाकिस्तान-पंजीकृत, पाकिस्तान द्वारा संचालित अथवा पाकिस्तान से लीज पर लिए गए सभी नागरिक और सैन्य विमानों के लिए भारतीय वायु क्षेत्र (एयरस्पेस) को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध आगे की समीक्षा तक प्रभावी रहेगा और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीं ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। इस निर्णय की जानकारी संबंधित अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन एजेंसियों और हवाई अड्डों को भी दे दी गई है।

भारत के इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान की वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों पर पड़ेगा। इस फैसले को भारत की तरफ से एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उकसावे की स्थिति में भारत सख्ती से जवाब देगा। पिछले कुछ दिनों से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार संघर्षविराम उल्लंघन और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों ने हालात को और भी नाजुक बना दिया है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री ने नंगल डैम पर ताला लगाकर कंट्रोल हाथ में लेने का किया दावा

पंजाब में आआपा का हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)

चंडीगढ़

हरियाणा के साथ चल रहे जल विवाद के बीच आम आदमी पार्टी (आआपा) ने गुरुवार को पंजाब में केन्द्र व हरियाणा सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व आआपा के मंत्रियों, विधायकों तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया। आआपा नेताओं ने बीबीएमबी से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को केंद्र की भाजपा सरकार का पंजाब के साथ धोखा बताया है। शिक्षा मंत्री ने नंगल डैम पर कब्जा कर कंट्रोल अपने हाथ में लेने का दावा किया।

आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के सामने पानी आपूर्ति के मुद्दे पर अपनी सरकार का पक्ष रखा। आआपा के तमाम मंत्री जिला मुख्यालयों पर भाजपा के विरूद्ध प्रदर्शन में शामिल हुए। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और हरभजन सिंह ईटीओ के नेतृत्व में आआपा विधायकों और कार्यकताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के घर के बाहर प्रदर्शन किया।

आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार पंजाब का पानी जबरदस्ती हरियाणा को दे रही है। मंत्रियों ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देकर केन्द्र की भाजपा सरकार ने पंजाब के साथ धोखा किया है। मंत्रियों ने कहा कि हरियाणा पहले से ही अपना पानी प्राप्त कर रहा है। पंजाब के किसान पानी की हर बूंद के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब के किसानों से बदला ले रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केन्द्र सरकार की यह कार्रवाई पंजाब के हितों के खिलाफ है।

भाजपा महासचिव तरुण चुघ के घर के बाहर आआपा कार्यकताओं ने किया प्रदर्शन

रोपड़ में पंजाब के शिक्षा मंत्री तथा नंगल के विधायक हरजोत सिंह बैंस ने प्रदर्शन के बाद नंगल में जाकर डैम पर धरना दिया। यहां आआपा नेताओं ने दावा किया उन्होंने डैम से छोड़े पानी को कंट्रोल करने के लिए वहां के अधिकारियों से चाबियां ले ली हैं। उस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब पंजाब सरकार के आदेश अनुसार ही पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया कि हरियाणा को फालतू पानी बिलकुल नहीं देंगे।

केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आआपा नेताओं और कार्यकताओं ने पंजाब के भाजपा नेताओं के घरों की तरफ कूच करने का भी प्रयास किया। इस बीच चंडीगढ़ में पुलिस ने पंजाब भाजपा मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है।

संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देगी कांग्रेस : प्रतिभा सिंह

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के सख्त खिलाफ है और इसे कभी सफल नहीं होने देगी। वह गुरूवार को बिलासपुर में जिला स्तरीय संविधान बचाओ अभियान की शुरूआत के अवसर पर बोल रही थीं।

उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की बुनियाद पर भारत का लोकतंत्र टिका है, लेकिन भाजपा लगातार इस बुनियाद को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और संसद में राहुल गांधी जैसे नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें रोकने और परेशान करने के लिए बदले की भावना से काम कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत की है, जिसे पूरे संगठन को एकजुट होकर सफल बनाना है। उन्होंने इस अभियान को कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन बताया और कहा कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वे कार्यकताओं की भावनाओं को समझें और उन्हें पूरा महत्व दें, क्योंकि सरकारें कार्यकताओं के परिश्रम से बनती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर नई कार्यकारिणी गठित करेगी, जिसमें कर्मठ कार्यकताओं को पूरा मान-सम्मान मिलेगा।

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि राहुल गांधी की इस मांग को पहले भाजपा ने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब केंद्र सरकार को इसे मानना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सभी वर्गों को उनके अधिकार मिल सकेंगे और यही वजह है कि राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

संविधान बचाओ अभियान के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रतिभा सिंह ने बताया कि यह 10 मई तक जिला स्तर पर, 11 से 17 मई तक विधानसभा यानी ब्लॉक स्तर पर और 20 से 30 मई तक घर-घर जाकर चलाया जाएगा।

कुल्लू जिला के शारसी में सात मई को होगा 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे अध्यक्षता

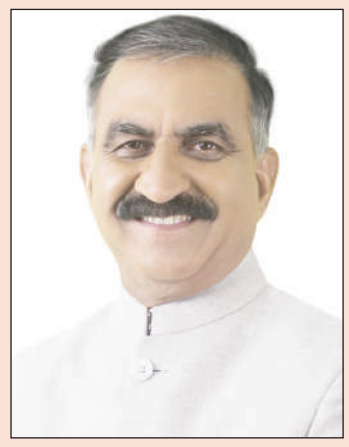

शिमला। प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू किए गए ह्यसरकार गांव के द्वारह्ल कार्यक्रम के तहत 7 मई को कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी के शारसी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। यह जानकारी गुरूवार को राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरूवार को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को मौके पर ही हल करने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने बताया कि अन्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रमों का शेड्यूल भी शीघ्र जारी किया जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार के लिए जन शिकायतों का समयबद्ध निवारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम से सरकार और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है जिससे न केवल समस्याएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं बल्कि उनका समाधान भी त्वरित रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है। मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लें और अपनी समस्याओं व सुझावों को प्रशासन के समक्ष रखें ताकि योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से उन तक पहुंच सके।

अंकुर सोनी बने बार एसोसिएशन कांगड़ा के अध्यक्ष, अक्षय ठाकुर महासचिव

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

बार ऐसोसिएशन जिला कांगड़ा धर्मशाला के चुनावों में अंकुर सोनी अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए आशु पटियाल और अंकुर सोनी के बीच मुकाबला हुआ जिसमें अंकुर सोनी को 260 जबकि आशु पटियाल को 104 मत ही मिले। इस तरह से अंकुर सोनी ने 156 मतों से जीत दर्ज की। 365 सदस्यों ने इस दौरान अपने मत का प्रयोग किया।

वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुमित चौधरी के सामने किसी भी उम्मीदवार के न होने पर उन्होंने निर्विरोध मनोनीत किया गया। इसके अलावा महासचिव पद पर तीन उम्मीदवारों अक्षय ठाकुर को 140, अमन पॉल को 111 व अमन लाल को 100 मत पड़े। जिसमें अक्षय ठाकुर ने 148 मतों से जीत दर्ज की। साथ ही सह-सचिव के पद पर दो उम्मीदवारों सुनील को 188 व विश्व वालिया को 164 मत हासिल हुए, जिसमें सुनील ने 22 मतों से जीत दर्ज की।

इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष अंकुर सोनी व चुने हुए पदाधिकारियों ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में ई-हाई कोर्ट के तहत ई-फाइलिंग यानी उच्च न्यायायल हिमाचल प्रदेश में ऑनलाईन ही केस फाईल करने के लिए रजिस्ट्री कांउटर खोलने के जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के सर्किट बैंच की मांग भी वर्षों पुरानी है, इसे भी पूरा करने की आवाज उठाएंगे। हालांकि रजिस्ट्री कांउटर खुलने से भी निचले हिमाचल के लोगों को बड़ा लाभ मिल पाएगा।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता प्रोफेशन में आने वाले नए लोगों को गाईड करने व उन्हें सुविधाएं प्रदान किए जाने सहित बार ऐसोसिएशन के विभिन्न समस्याओं व मांगों को हल करवाने के लिए काम किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा स्थगित फिलहाल नई तिथियों की घोषणा नहीं

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगामी 5 मई से 9 मई तक प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को औपचारिक सूचना भेज दी है। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दौरा स्थगित होने की पुष्टि की है। अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि राष्ट्रपति का यह दौरा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा, हालांकि नई तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मुर्मू को 5 मई को शिमला पहुंचना था। 6 मई को उनका कार्यक्रम सेना प्रशिक्षण कमान (आर.ट्रैक.) शिमला में प्रस्तावित था। इसके बाद 7 मई को उन्हें आईआईटी मंडी का दौरा करना था, जबकि 8 मई को वे अटल टनल रोहतांग देखने जाने वाली थीं। दौरे का समापन 9 मई को दिल्ली लौटने के साथ होना था।

राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर राज्य प्रशासन ने जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी थीं। 26 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक प्रदेश सचिवालय में आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया था। वहीं पिछले कल 30 अप्रैल को शिमला के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने भी प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की थी।

प्रशासन की ओर से कल्याणी हैलीपैड से लेकर द रिट्रीट तक के मार्गों की मरम्मत के आदेश दिए गए थे ताकि राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही में कोई बाधा न आए। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष योजना तैयार की गई थी और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के लिए वैकल्पिक लैंडिंग साइट्स की व्यवस्था की गई थी।

हिमाचल में एक हफ्ते तक लगातार बारिश की चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव आया है। पहाड़ी इलाकों में गुरूवार को जहां बादलों ने डेरा डाल लिया है वहीं बारिश और तेज हवाओं की आशंका ने लोगों को सतर्क कर दिया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से कुछ राहत तो मिली है लेकिन आगामी एक सप्ताह तक मौसम के बिगड़े मिजाज ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 7 मई तक पूरे प्रदेश में खराब मौसम रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कई स्थानों पर अंधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार आज यानी एक मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा 2 मई से 6 मई तक हवाओं की गति और तेज होकर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। 7 मई को फिर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और यात्रा से पूर्व मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी है।

5 और 6 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं। यह बर्फबारी खासकर लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं और बारिश से जहां फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है वहीं बिजली आपूर्ति में भी बाधा आने की संभावना बनी हुई है। खासतौर पर खराब मौसम से मैदानी इलाकों में गेहूं की कटाई का कार्य प्रभावित हो सकता है।

बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि कुछ स्थानों पर तेज अंधड़ चली लेकिन इससे कहीं भी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। सियोबाग और बजुआरा में हवाएं 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं, जबकि ताबो और रिकांगपिओ में अंधड़ की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इन हवाओं से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली।

राज्य के तापमान की बात करें तो गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सुंदरनगर में यह 21.4, भुंतर में 18.1, कल्पा में 9.2, धर्मशाला में 16.8, उना में 20.5, नाहन में 16.7, केलांग में 5.5, सोलन में 18, मनाली में 12.7, कांगड़ा में 23.8, मंडी में 22.2, बिलासपुर में 21.9, हमीरपुर में 22.2, चंबा में 18.5, डल्हौजी में 16.1, जुब्बड़हट्टी में 19.1, कुफरी में 12.4, कुकुमसेरी में 7.2, नारकंडा में 10.2, भरमौर में 15.2, रिकांगपिओ में 12.8, सियोबाग में 16, धौलाकुआं में 23.2, बरठीं में 20.9 और बातो में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

फारूक ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार और सेना प्रमुख की दो-राष्ट्र सिद्धांत पर भड़काऊ टिप्पणियों की आलोचना की

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के पहलगाम क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा की और इसके लिए सुरक्षा चूक और जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने के पाकिस्तान के प्रयासों को जिम्मेदार ठहराया।

अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की दो-राष्ट्र सिद्धांत पर भड़काऊ टिप्पणियों की आलोचना की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सुरक्षा और खुफिया चूक का मामला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह पसंद नहीं आया होगा कि हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दो-राष्ट्र सिद्धांत के बारे में बोलकर उकसाया है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है तो यह बातचीत की मेज पर आएगा लेकिन बातचीत की मेज पर क्या होगा, यह केवल अल्लाह ही जानता है। फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ अधिनियम पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, विधेयक का कड़ा विरोध किया और सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। यह अभी भी एक मुद्दा है और हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं।

शांता कुमार ने पर्यटन निगम कार्यालय शिफ्टिंग का किया स्वागत

एजेंसी (हि.स.)
पालमपुर

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पर्यटन निगम के मुख्यालय को शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को प्रदेश के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

शांताकुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली को इस फैसले के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले को प्रदेश की ह्यपर्यटन राजधानीह्ल बनाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और यह स्थान अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, विशेष रूप से धौलाधार पर्वतमाला के चलते पूरे भारत के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से उभर सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने पालमपुर स्थित सौरभ वन विहार का विशेष रूप से उल्लेख किया जो कारगिल युद्ध के पहले शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की स्मृति में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन चुका है, जहां हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं।

शांता कुमार ने कहा कि एक करोड़ रुपये की लागत से सौरभ वन विहार में टॉय ट्रेन परियोजना शुरू की जा रही है। रेल लाइन बिछाई जा चुकी है और इंजन व बोगियां भी पहुंच चुकी हैं। शांताकुमार ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस महीने स्वयं पालमपुर आकर टॉय ट्रेन योजना का उद्घाटन करें।

आरोप

कांग्रेस ने अपने शासन में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया

सत्ता में रहकर कांग्रेस ने नहीं की जातिगत जनगणना, अब कर रही श्रेय की राजनीति : सुरेश कश्यप

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय का स्वागत करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जब केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जातिगत जनगणना की घोषणा की है, तब कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में जुट गई है, जबकि अपने कार्यकाल में उसने हमेशा इस विषय को टालने का काम किया।

शिमला में गुरूवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने जनगणना के साथ-साथ जातियों की गणना करने का जो निर्णय लिया है, वह ऐतिहासिक है और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह जनगणना पूरी पारदर्शिता से समाज के सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कभी जातिगत जनगणना की न तो आवश्यकता समझी, न ही इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। अब जब मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है, तब राहुल गांधी झूठे दावे कर श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छह दशकों तक दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं जातिगत आरक्षण और जाति आधारित गणना के विरोधी थे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया था कि वे जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

सुरेश कश्यप ने बताया कि 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया। उस समय गृह मंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह ने वीपी मंडल द्वारा की गई जातिगत जनगणना की मांग को खारिज कर दिया था। राजीव गांधी और उनके बाद यूपीए सरकार के दौर में भी केवल वादे किए गए, लेकिन जातिगत जनगणना पर कभी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने भले ही संसद में इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही हो, लेकिन नतीजा शून्य रहा। उस समय सिर्फ सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित सर्वे (एसईसीसी) हुआ, जिसमें भारी त्रुटियां थीं और वह भी पूर्ण जनगणना नहीं थी।

संक्षिप्त-समाचार

हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट कैम्प के लिए हिमाचल की मन्नत कौर का चयन

धर्मशाला। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा अंडर 15 महिला वर्ग के लिए आयोजित किये जा रहे हाई परफॉर्मेंस कैम्प के लिए हिमाचल की मन्नत कौर का चयन हुआ है। इस कैम्प का आयोजन 16 मई से 9 जून तक बैंगलोर में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को 15 मई को कैम्प स्थल पर पंहुचना होगा। इस हाई परफॉर्मेंस कैम्प के लिए चयनित मन्नत कौर हिमाचल के सोलन की रहने वाली हैं। उधर मन्नत के चयन पर एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की है।

बडगाम में यूएपीए मामले में डॉ. गुलाम नबी फई को अपराधी घोषित किया

बडगाम। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बडगाम पुलिस ने माननीय विशेष न्यायाधीश, एनआईए कोर्ट, बडगाम के माध्यम से डॉ. गुलाम नबी फई को अपराधी घोषित करने में सफलता प्राप्त की है। बडगाम के वडवान निवासी डॉ. फई, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में छिपे हुए हैं, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10, 13 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज एफआईआर नंबर 46/2020 में शामिल हैं। वारंट जारी होने के बावजूद, डॉ. फई लगातार गिरफ्तारी से बचते रहे, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालते रहे और कानून के तहत जवाबदेही से बचते रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके लगातार असहयोग और जानबूझकर खुद को छिपाने के प्रयासों के मद्देनजर, बडगाम पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक दलील पेश की। इस दलील पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने 30 अप्रैल, 2025 को डॉ. फई को अपराधी घोषित कर दिया। अदालत ने डॉ. फई को उद्घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर जम्मू और कश्मीर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। बडगाम पुलिस न्याय और गिरफ्तारी से बचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

पहलगाम आतंकी हमलाः एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते पहुंचे पहलगाम

पहलगाम। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जांच का जिम्मा संभालने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद दाते गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम पहुंचे और एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले रविवार को एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले का मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस से अपने हाथ में ले लिया था और इस घातक हमले की जांच शुरू कर दी थी जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। केंद्रीय आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय के आतंकवाद निरोधी और कट्टरपंथ निरोधी (सीटीसीआर) प्रभाग से जारी आदेश के बाद शनिवार देर रात औपचारिक रूप से एक नई एफआईआर दर्ज की थी क्योंकि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रतिनिधि, द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एनआईए ने घटना के पांच दिन बाद और अपनी टीम द्वारा हमले स्थल का दौरा करने और जम्मू-कश्मीर पुलिस को जांच में सहयोग देने के चार दिन बाद मामले को अपने हाथ में लिया। इस हमले को पिछले बीस सालों में इस क्षेत्र में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है।

8 वर्षीय बच्चा लोड कैरियर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल

कुलगाम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बलसू इलाके में गुरुवार सुबह एक 8 वर्षीय बच्चा लोड कैरियर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि बलसू निवासी अरहान उमर नामक लड़के को सड़क पार करते समय वाहन ने टक्कर मार दी। चालक ने घायल बच्चे को तुरंत प्रारंभिक उपचार के लिए कुलगाम जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए एसकेआईएमएस सौरा रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ट्रक ढलान से लुढ़क कर ट्रैक पर रुका, कुछ समय के लिए स्थगित की गई रेल सेवाएं बहाल

अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके में एक ट्रक के ढलान से लुढ़क कर ट्रैक पर रुकने के कारण गुरुवार को कुछ समय के लिए स्थगित की गई रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। एक अधिकारी ने कहा कि आज सुबह काजीगुंड में बनिहाल और काजीगुंड (हिलर) के बीच किलोमीटर 167/10-11 पर जेके02एटी-5895 पंजीकरण संख्या वाले एक ट्रक के ढलान से लुढ़क कर ट्रैक पर रुक जाने के बाद एहतियात के तौर पर रेल परिचालन रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद रेल सेवाओं की सुरक्षित बहाली सुनिश्चित करने के लिए निकासी कार्य शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि निकासी कार्य पूरा होने के बाद अब रेल सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं।

बनिहाल में सीएपीडी में तैनात एक लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

बनिहाल। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बनिहाल क्षेत्र में सीएपीडी में तैनात एक लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सीएपीडी विभाग के रात्रि चौकीदार शाहीलाल शौकत अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो तहसील आपूर्ति कार्यालय (टीएसओ) बनिहाल में तैनात है। बयान में कहा गया है कि यह मामला उन आरोपों की गुप्त जांच के बाद शुरू किया गया था जिनमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने स्वयं के नाम पर और साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। सत्यापन से पता चला कि आरोपी ने जम्मू के इसराराबाद में एक आलीशान दो मंजिला आवासीय घर, बनिहाल में एक और दो मंजिला घर, विभिन्न स्थानों पर कई भूखंड और लक्जरी वाहन सहित महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की है। इसके अतिरिक्त वित्तीय दस्तावेज और बेहिसाब संपत्ति का संकेत देने वाले सबूत भी मिले हैं बयान में आगे कहा गया है कि जांच के दौरान अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त किए गए और स्वतंत्र गवाहों और मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में सिधडा और बनिहाल में स्थित आरोपियों के आवासीय परिसरों में व्यापक तलाशी ली गई। इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान विभिन्न बैंकों की 16 चेक बुक और पांच पासबुक, विभिन्न स्थानों पर संपत्तियों से संबंधित भूमि दस्तावेज, अंतरराष्ट्रीय यात्रा इतिहास को दर्शाने वाला पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा नोट, वरिष्ठ अधिकारियों की तीन आधिकारिक रबर स्टैंप, जिनमें से एक सीएपीडी रामबन और टीएसओ बनिहाल के सहायक निदेशक की थी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। आगे की जांच जारी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी और मनगढ़ंत कहानिया फैलाने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को किया गिरफ्तार

बांदीपोरा। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को बांदीपोरा जिले से छह लोगों को गिरफ्तार किया है जो पिछले महीने 24 अप्रैल को कुलनार बाजीपोरा अजास में हुई मुठभेड़ के संबंध में अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से झूठी और मनगढ़ंत कहानियां प्रसारित करने में शामिल थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसमें शामिल सभी लोगों के आपराधिक कृत्य ने देश की सुरक्षा परिदृश्य को खतरे में डाल दिया है इसमें क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने की प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बांदीपोरा पुलिस ने उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये झूठी कहानियां प्रसारित की हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए बांदीपोरा पुलिस ने पुलिस स्टेशन बांदीपोरा में धारा 152 बीएनएस, 66 (एफ) आईटी अधिनियम के तहत एफआईआर नंबर 71/25 दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में छह व्यक्तियों की पहचान एजाज अहमद गोजर बनिया, अजास, सरताज अहमद मलिक, जफरान अहमद, बिलाल अहमद अल्ताफ अहमद वानी और बिलाल अहमद परे के रूप में हुई है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भूपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

मतदाता सूचियों के नवीनतम के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना होगा प्राप्त

बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है।

उन्होंने बताया कि आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (जैसा कि 2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर

- मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा

जानकारी मिल सके। इससे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को फॉर्म 7 के इंतजार के बिना फिल्ट विजिट के दौरान ही पुनः सत्यापित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी बदलाव करने का फैसला किया है। पर्चियों पर मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

इसके अलावा फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारी भी मतदाता सूची में मतदाता का नाम आसानी से ढूंढ सकेगा।

उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें।

उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करते समय बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज अटेली विधानसभा क्षेत्र को 6.39 करोड़ रुपये की लागत की 70 विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की सौगात दी।

कुमारी आरती सिंह राव ने कनीना में आयोजित कार्यक्रम में 3.94 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व 2.40 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा, उन्होंने जिला रेडक्रॉस व एलीम्को के सहयोग से 38 दिव्यांग व्यक्तियों को 4.62 लाख रुपये की लागत की इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल व अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए।

- 38 दिव्यांग व्यक्तियों को 4.62 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल व अन्य सहायक उपकरण किए वितरित

इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में प्राथमिक उपचार से लेकर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यह कार्य तो केवल ट्रेलर है। विकास की तस्वीर अभी बाकि है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाल ही में नागरिक अस्पताल नारनौल को एक करोड़ रुपए की लागत की ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन दी गई है, जिसमें ब्लड के विभिन्न कंपोनेंट तैयार किए जा सकेंगे तथा प्लेटलेट्स के अलावा डेंगू के मरीजों के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. विवेक भारती, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा, एसडीएम डॉ. जितेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

राजस्व मंत्री ने विद्यार्थियों को किया सम्मानित

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अच्छी शिक्षा और उससे संबंधित आधारभूत ढांचे उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार जानती है कि बच्चों का भविष्य अच्छी शिक्षा में ही है और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है।

वे चरखी दादरी में जनता कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दादरी एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय रामकिशन गुप्ता को नमन करते हुए कहा कि वे दूरगामी सोच के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1965 के समय में इस दादरी क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई।

उन्होंने कहा कि उस समय शिक्षा के बारे में सोच रखना अपने आप महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं का भविष्य

- अब बिना पर्ची खर्ची प्रतिभाओं को मिल रही नौकरी

संवारने की नींव रखी।

उन्होंने कहा कि केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की ओर कार्य किए गए हैं। सरकार जानती है कि बच्चों का भविष्य शिक्षा में ही है। इसी सोच को आगे बढाते हुए हरियाणा में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक महिला महाविद्यालय खोलने का कार्य वर्ष 2014 से ही शुरू कर दिया गया था।

सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था के साथ सरकार ने युवाओं को स्वर्णिम भविष्य का मौका दिया है। हरियाणा में अब प्रतिभावान युवाओं को नौकरी के लिए नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है।

दिल्ली में आप की सरकार थी तब तक पंजाब की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया: श्रुति चौधरी

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने हरियाणा-पंजाब के पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार से कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक पंजाब सरकार की ओर से पानी नहीं रोका गया अब जब दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास नहीं है तब ऐसा तमाशा कर रहे हैं।

मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बीबीएमबी की बैठक में पंजाब सरकार की ओर से किए गए अनुचित व्यवहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए क्योंकि हर साल जैसी व्यवस्था ही अब भी वैसी ही है तो फिर पंजाब सरकार की ओर से ऐसा ड्रामा

- सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने जल वितरण पर पंजाब सरकार से जताई कड़ी नाराजगी
- आम लोगों को परेशान करके तमाशा ना करें भगवंत मान सरकार

क्यों किया जा रहा है। भगवंत मान सरकार को समझना चाहिए कि वे आम लोगों को परेशान ना करें।

श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ने जल में जहर मिलाने की बात कही थी उसी राह पर चलते हुए भगवंत मान ने अपने पद की गरिमा ना रखते हुए पानी रोकने का काम किया गया। यह पानी पूरी तरह से बीबीएमबी का है यही पानी हरियाणा से दिल्ली और राजस्थान भी जाता है फिर वापिस पंजाब भी आता है। दिल्ली की सरकार नहीं रही तो यह तमाशा इनकी ओर से किया गया है। यह मामला कुछ दिनों का था पर लोगों को परेशान करना भगवंत मान सरकार की मंशा रही है।

शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक साधना भी है: बंडारू दत्तात्रेय

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल व चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है। निरंतर सीखते रहने का नाम साधना है। सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए, निरंतर सीखने, मेहनत करने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यह सफलता व संतुष्टि दोनों में सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नई तकनीकों, कौशल विकास के साथ-साथ चरित्रवान, शीलवान तथा आशावादी बनने का आह्वान किया। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय वीरवार को भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह में श्री दत्तात्रेय ने 1276 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें 43 छात्राएं शामिल थी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की तरफ से साउथ एशियन पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा को समाज में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 10 साल की विकास गाथा पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया।

बेल्ट रेसलिंग व मास रेसलिंग नेशनल फेडरेशन कप प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए खिलाड़ी

अनिल गोयल
लाडवा

एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हरियाणा की तरफ से खिलाड़ियों को जयपुर में आयोजित होने वाली बेल्ट रेसलिंग व मास रेसलिंग नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप के लिए रवाना किया गया। एसोसिएशन के महासचिव सतविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से 4 मई तक राजस्थान के जयपुर में 4 दिवसीय नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप 2025 आयोजित की जानी है जिसमें हरियाणा की ओर से भी 49 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनकी रवानगी के लिए एसोसिएशन ऑफ ट्रेडीशनल स्पोर्ट्स हरियाणा की तरफ से एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यातिथि के रूप में एसोसिएशन के चेयरमैन अमित खुराना शामिल हुए व अध्यक्षता एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट राकेश खुराना ने की। मुख्यातिथि अमित खुराना ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में क्षेत्र का खेलों में प्रतिनिधित्व करना ना केवल खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है बल्कि पूरी एसोसिएशन के लिए हर्ष का विषय है और इस चैंपियनशिप के लिए उन्होंने खिलाड़ियों से अपना शत-प्रतिशत देने की अपील की। कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश खुराना ने रेसलिंग खेल के बारे में बताते हुए कहा कि इस खेल को सरकार की खेल नीति में शामिल कराने के लिए उनकी एसोसिएशन प्रयासरत है ताकि इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों को फायदा मिल सके। एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रधान अमित सिंघल, दून पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या अनीता शर्मा व उपप्रधानाचार्या कुसुम मित्तल ने भी खिलाडियों को शुभकामनायें देकर विदा किया। इस अवसर पर अनूप सांगवान, सरदार करनैल सिंह, कोच अमित धारीवाल, रश्मि धारीवाल, टीम मैनेजर अमनदीप सिंह, अरविन्द पंजेटा, रामकरण, जोवर, युग्म, रवनीत, वीरेन, हरमन, मनीष, वणिका, जीविका व हरप्रीत सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी, स्कूल स्टाफ, खिलाडी व अभिभावक उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित

संवाददाता
लाडवा

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में संजय गांधी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल द्वारा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं कॉमर्स के छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना और छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना था।

प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचारों को रंग-बिरंगे और विचारोत्तेजक पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत किया। बारहवीं कॉमर्स की आयुषी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बारहवीं कॉमर्स की परनीत को द्वितीय स्थान मिला। तृतीय स्थान ग्यारहवीं कॉमर्स की त्रिप्ती को प्राप्त हुआ।

बारहवीं कॉमर्स के करण को उनके सराहनीय प्रयास और रचनात्मकता के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और छात्रों की रचनात्मकता व जागरूकता की सराहना की। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने प्रतिभागियों का उत्साह और भी बढ़ा दिया।

कार्यक्रम में विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण – राजबीर शर्मा, अजय कुमार, संजीव कुमार, पूनम शर्मा, परमजीत कौर, कविता लालर एवं रणदीप कौर - भी उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

निरीक्षण

चार महीनों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मारे गए 28 छापे

एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर होगा लाइसेंस रद्द : सुधीर राजपाल

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की बैठक हुई, जिसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई तथा राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई।

उन्होंने सभी सी.एच.सी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यू.पी.एच.सी.) के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एस.एम.ओ.) को निर्देश दिए हैं कि वे लिंग अनुपात में सुधार के लिए की जाने वाली गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनें। सी.एच.सी. और यू.पी.एच.सी के प्रभारी एस.एम.ओ. को उनके क्षेत्र के लिंग अनुपात में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जिन महिलाओं को पहले से ही लड़की है और जो आईवीएफ के लिए जा रही हैं, उनसे संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) केंद्रों द्वारा लिंग चयन की संभावना को समाप्त किया जा सके। सिविल सर्जनों को जिले में निजी प्रैक्टिस करने वाली सभी महिला बीएएमएस/बी.एच.एम.एस. डॉक्टरों की लाइन लिस्ट बनानी चाहिए ताकि अवैध गर्भपात की जांच की जा सके और सभी डीएंडसी मामलों को रेट्रो ट्रैक किया जाना चाहिए।

हरियाणा के डीजीएचएस डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में सभी गांवों के लिंगानुपात को लक्षित दृष्टिकोण के लिए संकलित किया गया है और 700 से कम लिंगानुपात वाले 481 गांवों में 25 अप्रैल, 2025 को

विशेष बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ शिविर आयोजित किए गए।

राज्य टास्क फोर्स के संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि एमटीपी केंद्रों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण किया जा रहा है और दो जीवित लड़कियों वाली गर्भवती महिला का एमटीपी करने वाले किसी भी केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। कुल 1500 एमटीपी केंद्रों में से 384 एमटीपी केंद्रों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। 30 एमटीपी केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं। पिछले चार महीनों में यानी जनवरी से अप्रैल 2025 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएनडीटी एक्ट के तहत 28 छापे मारे गए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर 18 से 29 अप्रैल, 2025 तक बालिकाओं के जन्म पर 1500 कुआं पूजन समारोह आयोजित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), रायपुर रानी, पंचकूला के अंतर्गत उप-केंद्र, हंगोला की बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू)-महिला को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बैठक में डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया कि एमटीपी किट की बिक्री राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा केवल पंजीकृत एमटीपी केंद्रों तक ही सीमित कर दी गई है। 17 ऑनलाइन एमटीपी किट विक्रेताओं और 2 बिना लाइसेंस वाले एमटीपी किट विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 29 अप्रैल, 2025 को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर (डीसीओ) कैथल द्वारा हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एच.एस.एन.सी.बी.) के साथ कैथल में आवासीय परिसर में छापेमारी की गई, जहां से 5805 एमटीपी किट बरामद की गईं। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सिटी कैथल में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एमटीपी किट की बिक्री में गिरावट का रुझान है। शहरी क्षेत्रों में सभी वार्ड (क्षेत्र) को डेटा संग्रह (पुरुष और महिला शिशु जन्म) और लिंग अनुपात में सुधार के उद्देश्य से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी)/शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यूएएएम) की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) को आवंटित किया गया है।

उन्होंने बताया कि एक या एक से अधिक जीवित लड़कियों वाली 62,000 गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है, और इन गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है। आशा को ह्यसहेली के रूप में गर्भवती महिलाओं के साथ जोड़ा जाएगा तथा बालिका के सफल प्रसव के लिए एनएचएम हरियाणा द्वारा संबंधित आशा को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। एक या अधिक जीवित बालिकाओं के बाद पुत्र को जन्म देने वाली महिलाओं को पूर्वव्यापी ट्रैकिंग कॉल की जा रही है, ताकि लिंग पहचान/लिंग चयन गतिविधि का पता लगाया जा सके।

संक्षिप्त-समाचार

ग्लोब हेरिटेज में मनाया गया श्रमिक दिवस

लाडवा। ग्लोब हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में श्रमिक दिवस धूम धाम से मनाया गया। स्कूल प्रधानाचार्या रीतू सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल परिसर में श्रमिक दिवस धूम धाम से मनाया गया जिसमें प्रबंधक समिति की तरफ से सहयोगी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया व बच्चों ने अपने बनाये हुए धन्यवाद कार्ड भेंट कर सभी का धन्यवाद किया। प्रबंधक समिति की प्रधान रंजना गोयल ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनायें देते हुए कहा कि वर्तमान युग में हर इन्सान एक श्रमिक है क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जीवन में सफल होने के लिए मेहनत का होना अत्यंत आवश्यक है। स्कूल की प्रधानाचार्या रीतू सिंगला ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और आप लोगों के बिना किसी भी काम की कल्पना करना नामुमकिन है।

बिजली वितरण निगम निर्बाध बिलजी आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध

चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ह्यूपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टिह्ल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05, 12, 19 और 26 मई को जोनल पंचकूला में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।

हिंदू हाई स्कूल में मनाया गया मजदूर दिवस

लाडवा। हिंदू हाई स्कूल में मजदूर दिवस मनाया गया। प्रबंधक कमेटी के प्रधान पवन गर्ग ने स्कूल के ड्राइवर , स्वीपर, सफाई कर्मचारी व गार्ड को उनकी कर्तव्य निष्ठा,ईमानदारी व काम के प्रति लगन को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया। स्कूल की प्रधानाचार्य योगिता आलहुवालिया ने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे समाज व देश के विकास के लिए मजदूरों का अहम योगदान होता है । उन्होंने बच्चों को बताया कि मजदूर समाज के लिए हमेशा से सम्मानित रहा है। स्कूल के अध्यापक संदीप जी ने बच्चों को बताया कि हमें मजदूरों का सम्मान करना चाहिए । उन्हें आदर पूर्वक उनका मेहनताना देना चाहिए। मजदूर अपना काम पूरी मेहनत से करता है तो यह उसका हक होता है।उन्होंने बच्चों को बताया कि मजदूरों के महत्व को दर्शाने के लिए ही इस मजदूर दिवस को मनाने की शुरूआत की गई थी। मजदूर हमेशा ही अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहा है। राष्ट्र के विकास के लिए मजदूर विशेष योगदान देता है। इसलिए वह सम्मान व आदर के योग्य होता है। उन्होंने बच्चों को समझाया की मेहनत करने वाला छोटा नहीं होता बल्कि वह काम को करने के लिए खून , पसीना बहा देता है। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं व छात्रगण उपस्थित रहे।

ऊर्जा विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा नई लिफ्ट का पंजीकरण 30 दिन के अन्दर जबकि लिफ्ट का नवीनीकरण 15 दिन के अन्दर किया जाएगा। इन दोनों सेवाओं के लिए कार्यकारी अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए मुख्य बिजली निरीक्षक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

किड्जी स्कूल में कर्मचारियों को सम्मानित किया

लाडवा। किड्जी स्कूल में श्रमिक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी कर्मचारियों – सफाई कर्मचारी, आया दीदी, गाइर्स ,ड्राइवर और अन्य सहायक स्टाफ को सम्मानित किया गया और उनके निरंतर सहयोग और समर्पण के लिए धन्यवाद दिया गया।प्रधानाचार्य विम्मी तनेजा ने सभी गैर शिक्षण कर्मचारी को उपहार देकर सम्मानित किया। छोटे बच्चों द्वारा तैयार किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य और कविताओं के माध्यम से श्रमिकों के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता को व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य विम्मी तनेजा ने कहाह्लहमारे स्कूल का संचालन और बच्चों की देखभाल केवल शिक्षकों से नहीं बल्कि पूरे स्टाफ के सामूहिक प्रयास से संभव होती है। आज का दिन उन सभी श्रमिकों के सम्मान का दिन है जो हर दिन निष्ठा से अपना कार्य करते हैं। हमारे बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि हर काम का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी भूमिका क्यों न हो।ह्व किड्जी स्कूल परिवार की ओर से सभी श्रमिकों को श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं।इस मौके पर मुस्कान मग्गो, गीता शर्मा ,गीता, सोनिया,विशाखा,अदिति, कविता,स्वाति ,गरिमा,श्रेया, शिवानी,मुस्कान,प्रीत,भावना, पल्लवी, शैल्वी,पल्लवी शर्मा,महक ,नेहा,सिमरन खुशी,डॉली,मंजू , निशू आदि अध्यापिका शामिल हुई।

ग्राफिक डिजाइन कोर्स को पाठ्यक्रम में किया गया शामिल

लाडवा। लाडवा के सुगनी देवी आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्या पूजा छाबड़ा ने बताया कि स्कूल में ग्राफिक डिजाइन कोर्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया` ग्राफिक डिजाइन छात्रों में कलात्मक कौशल और रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करता है उन्होंने कहा कि यह कोर्स विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और नए डिजाइन बनाने का अवसर प्रदान करता है और कलात्मक प्रतिभा को उजागर करने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करता है` आज के समय को देखते हुए ग्राफिक डिजाइन में करियर के बहुत सारे अवसर हैं विद्यार्थी विज्ञापन ,वेबसाइट डिजाइन, प्रिंट मीडिया या एनीमेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और विद्यार्थी इसके द्वारा भविष्य में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।

संपादकीय

भारत की औद्योगिक क्षमता को पुनर्जीवित करना समय की मांग

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की औद्योगिक विकास दर वर्ष 2025 में मात्र 4% पर पहुँच गई है—यह पिछले चार वर्षों का न्यूनतम स्तर है। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में गिरावट तथा निर्यात में सुस्ती के चलते आई है। खासकर टरटए सेक्टर पर दबाव बना हुआ है, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 45% योगदान करता है। ऐसे में औद्योगिक पुनर्जीवन आज केवल आर्थिक प्राथमिकता नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन गया है।आइये समझते हैं औद्योगिक विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख घटकों को। भारत सरकार ने 'मेक इन इंडियाश्र, 'आत्मनिर्भर भारत' और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों से विनिर्माण क्षेत्र को गति देने का प्रयास किया है। इन योजनाओं ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, और भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई है।पी एल आई योजना के चलते पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र में एफ डी आई प्रवाह 69% बढ़ा और यह रु 14.45 लाख करोड़ (यू एस डॉलर165.1 बिलियन) तक पहुँच गया। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का लक्ष्य जी डी पी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 2025 तक 25% तक बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू निवेश रु 37 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो उद्योगों में बढ़ते विश्वास को दशार्ता है। साथ ही, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में एफ डी आई में वृद्धि हुई है। भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र वैश्विक कंपनियों के लिये आकर्षण का केंद्र बन रहा है, विशेषकर ई वी निर्माण में। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2015 से 2024 तक 17.5% की सी ए जी आर दर्ज की गई है।भारत की विनिर्माण इकाइयाँ तेजी से ए आई, आई ओ टी, स्वचालन और रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को अपना रही हैं। इससे उत्पादन दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार आया है। एच एस बी सी मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई मार्च 2024 में 59.1 रहा, जो 16 वर्षों में सर्वोच्च स्तर है। 'मेक इन इंडिया 2.0' पहल के अंतर्गत तकनीक-सक्षम एस एम ई हब की स्थापना की जा रही है। भारत का मध्यम वर्ग 2030 तक वैश्विक उपभोग का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है।इस समूह की क्रय शक्ति ऑटोमोबाइल, एफ एम सी जी, स्मार्ट डिवाइसेज और दवाओं जैसी वस्तुओं की माँग को आगे बढ़ा रही है।उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का विकास वित्त वर्ष 2025 में 8% पर पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 3.6% था। भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2024 में 6% बढ़ा। भारत सरकार की पी एम गति शक्ति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, भारतमाला योजना और पी एम आवास योजना जैसी पहलों ने औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत किया है।कच्चे इस्पात उत्पादन में अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट उद्योग को राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं से नया जीवन मिला है। भारत की रणनीतिक स्थिति इसे इंडो-पैसिफिक और यूरोपीय बाजारों से जोड़ती है। देश इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का मोबाइल निर्यात 5 बिलियन डॉलर तक पहुँचा, जो 92% की वृद्धि दशार्ता है।राष्ट्रीय रसद नीति और मल्टी-मोडल हब परियोजनाओं के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के प्रयास जारी हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को औद्योगिक विकास का अभिन्न अंग बना लिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रु 20,000 करोड़ की राशि परमाणु व सौर परियोजनाओं के लिये आवंटित की गई। पी एम ई-ड्राइव योजना के चलते ई वी क्षेत्र में अभूतपूर्व उछाल देखा गया है।गर हम बात करें औद्योगिक विकास में बाधाएँ और संरचनात्मक चुनौतियों की तो मुद्रास्फीति, टैरिफ युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों ने भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है। आई एम एफ ने भी भारत की 2025-26 की विकास दर को घटाकर 6.2% कर दिया है। अमेरिका के टैरिफ्स से भारत को डॉलर 14 बिलियन का निर्यात घाटा हो सकता है। चीन से आयात पर निर्भरता भी आपूर्ति सुरक्षा के लिये खतरा है। शहरी विकास के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति कमजोर बनी हुई है। ग्रामीण उपभोग में गिरावट से एफ एम सी जी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उपकरण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। दिसंबर 2024 में ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 8.65% रही, जबकि शहरी दर 7.9% थी। बचत की प्रवृत्ति बढ़ने से विवेकाधीन खर्च में कटौती हुई है। यद्यपि कई सुधार किए गए हैं, फिर भी रसद लागत ऊँची है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अब भी जी डी पी का 14-18% है, जबकि विकसित देशों में यह 8-10% के बीच है। औद्योगिक गलियारों, एम एम एल पी और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करना आवश्यक है। एम एस एम ई सेक्टर को कई बार अनुमति, रजिस्ट्रेशन और टैक्स अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में भारत की रैंकिंग में सुधार के बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार अपेक्षित है।भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और श्रम कानूनों के सरलीकरण की आवश्यकता है। एकल खिड़की प्रणाली का क्रियान्वयन अधिकांश राज्यों में अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यह भी सच है कि भारत के 60 मिलियन एम एस एम ई लगभग 25 करोड़ नौकरियाँ प्रदान करते हैं। इन्हें संरचनात्मक समर्थन देना न केवल आवश्यक है, बल्कि दीर्घकालिक विकास के लिये अनिवार्य भी। क्रेडिट गारंटी फंड, डिजिटल क्रेडिट रेटिंग और ई-मार्केटप्लेस को सरल बनाया जाना चाहिए। निर्यात उन्मुख एम एस एम ई के लिये विशेष जोन और क्लस्टर आधारित रणनीति अपनाई जा सकती है। भारत को इनोवेशन ड्रिवन इकॉनमी बनाना होगा। इसके लिये अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को अधिक निवेश करना होगा। स्टार्टअप इंडिया, एटलब इनोवेशन मिशन, और डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स को उद्योगों से जोड़ा जाए। स्किल इंडिया कार्यक्रम में ई वी, ए आई और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिये विशेष प्रशिक्षण मॉडल शामिल हों। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप, हरित औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाए। ग्रीन टैक्स इंसेंटिव, ईको-फ्रेंडली फैक्ट्रियाँ और कार्बन क्रेडिट मार्केट की नीति को गति दी जाए। ईएसजी मेट्रिक्स को बड़े उद्योगों के साथ-साथ एम एस एम ई के लिये भी अनिवार्य किया जाए। अंत में कह सकते हैं कि भारत की औद्योगिक नीति को केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे नवाचार, संधारणीयता, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ना होगा। औद्योगिक विकास के साथ यदि हम समावेशिता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करें, तो यह न केवल भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी देश को निर्णायक भूमिका में लाएगा। भारत की औद्योगिक पुनरुत्थान यात्रा अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है।

रेटपेयर्स की सक्रिय भागीदारी से ही अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (हि.स.)

आज हमारी अर्थव्यवस्था भले विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो व जीडीपी रैंकिंग में इस साल हम विश्व की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में हों पर अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए रेटपेयर्स की भागीदारी बढ़ाने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फ्रीबीज के जमाने में केन्द्रीय वित्त सचिव अजय सेठ द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रेटपेयर्स को प्रोत्साहित करना जरुरी बताया गया है।

दरअसल, एक ओर राजनीतिक दलों द्वारा लोक लुभावन फ्रीबीज सुविधाओं की घोषणाएं-दर-घोषणाएं की जा रही हैं तो दूसरी ओर देश को 2025 में जीडीपी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती है। अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा गणित यह है कि एक तो करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कर के रुप में सीधे-सीधे आय सरकार को प्राप्त होती है तो दूसरी ओर सरकार अपनी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उधारी से काम चलाने वाली स्थिति होती है जिसे हम बजट प्रस्तावों में उधारी के रुप में देखते हैं। तीसरा प्रमुख स्रोत रेटपेयर्स होते हैं, देश का सेविंग पूल इन्हीं से बनता है।

जहां तक आयकर का प्रश्न है तो आधार और पैनकार्ड के चलते अब आयकर के दायरे से कोई बच नहीं सकता। खासतौर से नौकरीपेशा या निश्चित पगार पाने वालों का तो आयकर सीधे-सीधे और बिना किसी छीजत के सरकार को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी तरह की चोरी की संभावना न के बराबर है। लगभग यही स्थिति जीएसटी के बाद देखने को मिल रही है और साल दर साल जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी भी हो रही है।

दरअसल, जब स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी तो उसके साथ यह भी था एक समय आते-आते यह संस्थाएं अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो जाएंगी और इन संस्थाओं को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर एक ओर यह सपना ही बनकर रह गया दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का ऐसा चलन चलाया कि रेटपेयर्स की भूमिका कम से कम होती जा रही है।

रेटपेयर्स का प्रयोग सबसे पहले 1845 में माना जाता है। रेटपेयर्स की भूमिका को हम इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि न्यूजीलैण्ड सहित अनेक देशों में तो रेटपेयर्स अपने हितों की रक्षा के लिए एसोसिएशन बनाकर आगे आ रहे हैं। हमारे देश में हालात इससे विपरीत है। हमारे यहां पिछले कुछ सालों में रेटपेयर्स की सहभागिता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। केन्द्रीय वित सचिव अजय सेठ के अनुसार संभवतः यही चिंता का कारण बन रहा है।

रेटपेयर्स से सीधा-सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरे में आती हैं। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरे में प्रमुखता से ला रही हैं। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन संवेदनशील और लोकहितकारी सरकार के लिए आवश्यक है। पर इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो राशि कर या अन्य रुप में प्राप्त की जाती है वह नहीं मिले और उसका भार भी ईमानदार कर दाताओं पर पड़े तो यह किसी भी हालत में सही नहीं है। सरकार को सक्षम और कम सक्षम में अंतर करके चलना होगा। केन्द्रीय वित सचिव की मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि फ्रीबीज के कारण जो रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है उसपर ध्यान देना आवश्यक है।

इसमें दो राय नहीं कि समाज की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सहायता दी जाए पर यह नहीं होना चाहिए कि मुख्यधारा से वंचित के नाम पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोगों या परिवारों को भी यह सुविधाएं दी जाए। इससे होता यह है कि जो आम करदाता है वह तो अपने आपको ठगा महसूस करता ही है, कहीं ना कहीं समाज में गैप भी बढ़ता है। आर्थिक विकास में जो जनभागीदारी होनी चाहिए वह भी बाधित होती है। ऐसे में फ्रीबीज की राजनीति के बीच रेटपेयर्स की भागदारी को भी बढ़ाना होगा जिससे अर्थव्यवस्था का मल्टिपल विकास संभव हो सके। आज के लाभार्थियों को भी अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में समझना होगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

खेलो इंडिया में दिखेगा बिहार का दमखम

अजय पांडेय (हि.स.)

विकास के साथ जिस सर्व-समावेशिता की बात आज विश्व बैंक से संयुक्त राष्ट्र तक हर मंच पर होती है, उसके लिए हो रहे प्रयास देश के संघात्मक ढांचे की नई चमक को जाहिर कर रहे हैं। इस लिहाज से सबसे दिलचस्प है खेलों की दिशा में राज्यों का शानदार प्रदर्शन। जिस आयोजन की आज पूरे देश में चर्चा है, वह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इस बार यह अहम आयोजन न सिर्फ बिहार में हो रहा है बल्कि प्रदेश के पांच शहरों में इससे जुड़ी खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये शहर हैं- पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय।

बिहार जैसे सूबे में इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल आयोजन के मायने गहरे और बहुस्तरीय हैं। कुछ दशक पहले तक बिहार वैसे राज्यों में शुमार होता था, जिसके विकास की संभावनाओं पर लगातार नकारात्मक तरीके से विचार किया गया। दरअसल, इस पूरे संदर्भ का आगाज 1980 के दशक में तब हुआ, जब जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। बोस ने इस रिपोर्ट में देश के चार बड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ह्यबीमारूह्न राज्य बताया। पर बीते दशकों में यह स्थिति लगातार बदली है।इस दौरान विकास को लेकर इन राज्यों के विकास का नया चरित्र उभरा है।

बात अकेले उस सूबे की करें जहां इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेगा आयोजन हो रहा तो यह इस सूबे की खेल संस्कृति और उस दिशा में हो रही प्रगति की ओर स्वभाविक तौर पर ध्यान ले जाता है। आज की तारीख में ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं के लिए मशहूर बिहार खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी में बिहार का दमखम खासतौर पर दिखा है। बिहार की दृष्टि से यह बड़ा बदलाव है।

खेलों की मेजबानी में बिहार को प्राथमिकता मिलने के पीछे कई अहम कारण हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने बीते दो दशकों में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि राजगीर को एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

खेलों के आयोजन से बिहार जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिल रहा है। दरअसल, जब कहीं भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है, वहां हजारों खिलाड़ियों, कोच, आयोजकों और दर्शकों का आगमन होता है।इससे होटल, रेस्तरां, परिवहन, लोकल मार्केट और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में पटना में आयोजित राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 40 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ हुआ।

खेल आयोजनों से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। खेलों को बढ़ावा देने वाले राज्य में कॉरपोरेट कंपनियां, स्पॉन्सर और खेल ब्रांड निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। बिहार में अब कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे खेल उपकरण उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे न केवल राज्य की जीडीपी को मजबूती मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए करियर के नए विकल्प खुलेंगे।

राज्य में अब नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिल रहा है। पहले उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और मौके के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बिहार के उभरते हुए एथलीटों को अपने घर के नजदीक विश्वस्तरीय कोचिंग और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है।

बिहार में खेल आयोजनों की सफलता से राज्य की वैश्विक पहचान भी बन रही है। स्वाभाविक तौर पर जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होता है तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा होती है। इससे बिहार की छवि आधुनिक, प्रगतिशील और खेल-समर्थक राज्य के रूप में बनती है। पहले बिहार को केवल प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता था लेकिन अब इसे खेलों की नई राजधानी के रूप में भी देखा जा रहा है।

खेल आयोजनों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बिहार पहले ही बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक विरासत के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित होती हैं, तो इससे यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। खेल आयोजनों के दौरान पर्यटक न केवल मैच देखने आते हैं बल्कि वे स्थानीय बाजारों, हस्तशिल्प उद्योग और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करते हैं। इससे बिहार की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलता है।

खेल आयोजनों से राज्य में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकास भी तेज हो रहा है। खेल सुविधाओं के निर्माण, स्पोर्ट्स गियर मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस और कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। बिहार सरकार ने खेल नीति 2023' के तहत खेल-केंद्रित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है, जिससे युवा उद्यमियों को खेल से जुड़े व्यापार में कदम रखने का अवसर मिलेगा।

अगर बिहार में खेलों के महत्वपूर्ण आयोजन इसी तरह होते रहे तो आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक बन सकता है। इससे जहां खेल स्पधाओं से जुड़े रोजगार के अवसर और पर्यटन का विकास होगा बल्कि निवेश में वृद्धि आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।इस तरह की बढ़त और अनुकूलताओं से बिहार की छवि तो सुधरेगी ही, राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित होने का भी मौका मिलेगा।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज आपके अच्छे संबंधों से कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावनाएं हैं। छोटे भाई-बहनों की सफलता से मन प्रसन्न होगा। ऑफिस में सहकर्मियों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कारोबार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है।

वृषभः दिन उत्साह से भरा रहेगा और महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे। संपत्ति में निवेश के योग हैं। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक बातचीत फायदेमंद रहेगी। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है, साथ ही कार्यस्थल पर सहयोग भी मिलेगा।

मिथुनः विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। आज के दिन आपको संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। पारिवारिक तालमेल बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। सभी काम सुचारू रूप से पूरे होंगे।

कर्कः नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को थोड़ी चिंता हो सकती है। आज के दिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, सामान चोरी होने की आशंका है। क्रोध और घमंड से दूर रहें। संयम से कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित है।

सिंहः अचानक यात्रा का योग बन सकता है। शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें। करीबी रिश्तेदारों पर अधिक भरोसा करने से बचें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट संबंधी परेशानियों से।

कन्याः निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आज के दिन पुराने शत्रु भी मित्र बन सकते हैं। मेहनत से लक्ष्य प्राप्ति संभव है। परिवार के साथ आनंददायक समय बितेगा। अपनी कला और प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा।

तुलाः कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ रह सकती हैं, लेकिन आप उनका सामना कर पाएंगे। घर में मेहमान आने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

वृश्चिकः दिन की शुरूआत थोड़ी धीमी हो सकती है। आज के दिन विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दें। आज कि दिन धार्मिक या शुभ कार्यों में धन खर्च होगा। व्यापार में ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखें। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

धनुः विरोधी आलोचना कर सकते हैं, जिससे तनाव रहेगा। आज के दिन बापका छोटी यात्रा का विचार बन सकता है। गले की समस्या से सावधान रहें। अवैध संबंधों से परेशानी हो सकती है, संयम और सतर्कता आवश्यक है।

मकरः कार्यक्षमता में इजाफा होगा। आज के दिन आपके पास भविष्य की योजनाएं बनाने का समय है। किसी मांगलिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। आज विद्यार्थी एकाग्र रहेंगे। आज आपके लिए अचानक आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

कुंभः आज के दिन इआपकी वैवाहिक जीवन की उलझनें सुलझेंगी। आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। ऑफिस में सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन गर्मी से सेहत प्रभावित हो सकती है। संतान को लेकर चिंता रहेगी।

मीनः परिवार के कुछ सदस्य आपकी बातों को हल्के में ले सकते हैं। आज के दिन आप जिद्दी रवैये से बचें। थकावट और कमजोरी हो सकती है। भावनात्मक रूप से सतर्क रहें। एलर्जी व खाँसी की समस्या उभर सकती है।

पहलगाम त्रासदी

धुर्जति मुखर्जी

पहलगाम में हाल ही में 26 पर्यटकों की हत्या को मीडिया द्वारा जिस तरह से पेश किया गया, वह इस बात का संकेत है कि देश में धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जहां स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की एकता की बात की थी और महात्मा गांधी ने इस बात की वकालत की थी कि कैसे विभिन्न धर्म सत्य, भाईचारे और प्रेम के एक ही मार्ग की ओर इशारा करते हैं। दुख की बात है कि आज मानवता धार्मिक सिद्धांतों की प्राथमिक चिंता नहीं रह गई है; एक तरफ इनका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने वोट बटोरने के लिए धर्म को राजनीति में शामिल कर लिया है! हिंदू-मुस्लिम विभाजन को खत्म किया जाना चाहिए।

मुस्लिम युवाओं का वर्तमान कट्टरपंथीकरण न तो कुरान से और न ही हदीस से प्रेरित है क्योंकि राजनेता उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करते हैं कि समुदाय को आतंक का उपयोग करके अपना वर्चस्व फिर से हासिल करना चाहिए। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति है। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों की निराशा और नकारात्मक सोच उन्हें हिंसा के ऐसे जघन्य हमलों की ओर ले जाती है, जिसकी अधिकांश दार्शनिकों और विद्वानों ने निंदा की है।

भारत में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, जहाँ युवाओं का एक बड़ा वर्ग राजनीतिक नेताओं द्वारा आक्रामक होने और कट्टरपंथ का आ'ान करने के लिए उकसाया जाता है। वे यह समझने में विफल रहते हैं कि मूल हिंदू धर्म विभिन्न मान्यताओं का संगम है और इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना है। अर्ध-शिक्षित होने के कारण, उनके पास नौकरी भी नहीं है और धार्मिक मामलों पर निर्णायक रुख अपनाने के लिए शास्त्रों की व्याख्या पढ़ने की क्षमता भी नहीं है। उपमहाद्वीप में आतंकवाद के बढ़ने का कारण आम आदमी को प्रभावित करने वाली आर्थिक तंगी हो सकती है। लेकिन ये प्रवृत्तियाँ समाज को प्रभावित कर रही हैं और देश के लिए अच्छी नहीं हैं।

दुनिया के कई हिस्सों में सिर उठा चुकी राजनीतिक हिंसा के सवाल पर आते हुए, राजनीति विज्ञानी मरे एडेलमैन का ज़िक्र करना जरूरी है, जिन्होंने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक द सिंबोलिक यूजेस ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत शुरूआत में ही एक बहुत ही प्रासंगिक टिप्पणी की थी। इसमें कहा गया हैः 'राजनीतिक इतिहास बड़े पैमाने पर सामूहिक हिंसा और काल्पनिक भय और उम्मीदों से निपटने के लिए विशाल संसाधनों के व्यय का लेखा-जोखा है। साथ ही, लोगों का एक बड़ा वर्ग हानिकारक दमनकारी परिस्थितियों में शांत रहता है और कभी-कभी जोश के साथ उन्हीं सामाजिक संस्थाओं का बचाव करता है जो उन्हें वंचित या अपमानित करती हैं।'

पिछले कुछ सालों को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि भारत ने इस्लामी हिंसा को रोकने में अधिक सफलता हासिल की है। इसके मजबूत सुरक्षा तंत्र ने यह सुनिश्चित किया कि आतंकवाद पीछे रहे, और अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र को इस बात का डर बना रहे कि अगर वह उग्रवाद को कोई समर्थन देता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन पहलगाम में हुई यह भयावह त्रासदी खुफिया विफलता की ओर इशारा करती है क्योंकि आतंकवादियों ने एक भीड़भाड़ वाले पर्यटक स्थल को निशाना बनाया और बिना किसी गोली चलाए सुरक्षित निकल गए।

यह वास्तव में खेदजनक है कि विश्लेषकों का एक वर्ग भारत द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने की बात कर रहा है। इस समय ऐसा होना उचित नहीं है। सरकार ने पहले ही कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जो निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को प्रदर्शित करते हैं, और विपक्ष सरकार को पूरा समर्थन दे रहा है। सिंधु जल संधि को निरस्त करने का बदला पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करके लिया है, जिस पर बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

सरकार इस बात पर दृढ़ है कि इस तरह के आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीरियों ने एकजुट होकर हत्याओं की निंदा की है, खासकर इसलिए क्योंकि पर्यटकों को निशाना बनाना वर्जित है। व्यस्त पर्यटन सीजन से उनकी रोजी-रोटी चलती है और वे इस बात को लेकर आशंकित हैं कि इन भयानक हत्याओं का उस पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है।

साथ ही, यह भी जरूरी है कि सरकार सतर्कता और खुफिया नेटवर्क बढ़ाए। असमानता के बावजूद भारत की बढ़ती समृद्धि पाकिस्तान के लिए आंखों में खटक रही है, जो आतंकवादियों को भेजकर परेशानी पैदा करना चाहता है। इसके अलावा, पिछले साल से घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं और इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, वाशिंगटन को पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंधों को कम करने के लिए भारत से दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो हाल के महीनों में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बेचे गए अपने एफ-16 विमानों की निगरानी के लिए लगभग 400 मिलियन डॉलर जारी करने और जून में द्विपक्षीय आतंकवाद विरोधी वार्ता को फिर से शुरू करने की योजना के साथ आगे बढ़ा है। वाशिंगटन नई दिल्ली की चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखेगा, लेकिन ट्रम्प प्रशासन दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद हथियारों के निर्यात के बड़े हित का त्याग नहीं करेगा।

जबकि अमेरिका चाहता है कि हम ज्यादा रक्षा उपकरण बेचें, पाकिस्तान की सेना अपनी अहमियत जताने के लिए रक्षा बजट बढ़ाना चाहती है। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों के हितों के खिलाफ होगा। अगर सैन्य बजट बढ़ाया जाता है, तो इससे विकास संबंधी खर्च प्रभावित होंगे और समाज के निचले तबके पर असर पड़ेगा।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर का यह कथन कि उनका देश इस्लाम के नाम पर कश्मीर में संघर्ष का समर्थन करना जारी रखेगा, चर्चा में आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण को उचित ठहराया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अपरिवर्तनीय मतभेदों का उल्लेख किया, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया कि दोनों समुदाय एक साथ रह रहे थे और काम कर रहे थे। पाकिस्तान को एक कठोर राज्य कहना इस्लाम की विकृत कल्पना का स्पष्ट प्रतिबिंब था जो सामुदायिक भाईचारे, प्रेम और संबंध बनाने के अपने अंतर्निहित मूल्यों से बहुत दूर है।

मोदी ने आतंकवाद के दोषियों को सजा दिलाने की बात तो सही कही, लेकिन वे भारत की आत्मा और भारत की समृद्ध दार्शनिक परंपरा और संस्कृति को परिभाषित करने वाले मूल मूल्यों और विशेषताओं को स्पष्ट करने से चूक गए। जब नॉर्वे ने 2011 में ओस्लो हमले का सामना किया था, तो उसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश 'खुले, सहिष्णु और समावेशी' समाज के हमारे मूल्यों की रक्षा करने में दृढ़ रहेगा। हिंसा के प्रति इस प्रतिक्रिया की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि यह अधिक लोकतंत्र, अधिक खुलेपन और अधिक भाईचारे की बात करती है। धर्म एक निजी मामला है और इसे लोगों को एकजुट करने में बाधा नहीं बनना चाहिए। पहलगाम हत्याकांड से ठीक पहले उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की, इसका असली कारण समझ पाना मुश्किल है।

किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की जान लेना, उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जब हम धर्म और हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो किसी भी धर्म के शास्त्रों में ऐसी पागलपन भरी हत्याओं के बारे में नहीं लिखा है। नागरिक समाज को आतंकवादियों को पकड़ने और घाटी में शांति सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए खड़ा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को घाटी में वापस जाना चाहिए और इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। यह पड़ोसी को करारा जवाब होगा।

मान ने किया भाखडा नंगल डैम का दौरा

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के सीएम भवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार किसी को भी राज्य के पानी को लूटने की इजाजत नहीं देगी और इस बारे में पहले ही उचित योजना बनाई जा चुकी है। वे आज यहां भाखड़ा डैम कादौरा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी दमनकारी नीतियां पंजाब में नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने पानी को छीनने वाले ऐसे किसी भी कदम का जोरदार विरोध करेगा क्योंकि कृषि आधारित राज्य होने के नाते पंजाब का पानी हमारी जीवनधारा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि केंद्र ऐसी साजिशें रचने से पीछे नहीं हटा तो उसे यह भी भुला देना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पंजाब, देश को धान देगा।

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हरियाणा और राजस्थान को हर साल 21 मई से 20 मई तक पानी का बनता हिस्सा आवंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा इस साल मार्च महीने के अंत तक अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है जिसके कारण अब और पानी लेने के लिए पंजाब के पानी पर डाका डालने की बुरी चालें चल रहा है। इस बारे में विवरण साझा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब तक हरियाणा आवंटित पानी का 103 फीसदी उपयोग कर चुका है और अब भाजपा हरियाणा को और पानी देने के लिए पंजाब पर दबाव बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर दबाव के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उनका सरोकार पंजाब के किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि यह गैर-कानूनी चालें खेलने की बजाय केंद्र सरकार को पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद चिनाब, झेलम, उझ और अन्य नदियों के पानी को राज्य की ओर मोड़ना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस संधि के रद्द होने से बचाया गया अतिरिक्त पानी धान के सीजन से पहले जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे उत्तरी क्षेत्र को सप्लाई किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंजाब से अपील की थी कि उसके पास लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर पंजाब सरकार ने उदारता दिखाते हुए 6 अप्रैल, 2025 से हरियाणा को रोजाना 4000 क्यूसेक पानी देना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि पंजाब खेतों की सिंचाई के लिए पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है क्योंकि भूजल का स्तर गिर रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा हरियाणा और केंद्र की सरकारों के माध्यम से राज्य के साथ जबरदस्ती करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बी.बी.एम.बी. द्वारा पंजाब के पानी पर डाका डालने के लिए आए दिन नए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रही है ताकि राज्य के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है।

सीएम, सुदूरपश्चिम प्रांत, नेपाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद का दौरा किया

संवाददाता
फरीदाबाद

नवीकरणीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल करते हुए, कमल बहादुर शाह, माननीय मुख्यमंत्री, सुदूरपश्चिम प्रांत के नेतृत्व में नेपाल के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 1 मई 2025 को भारत सरकार के नवरत्न उद्यम एनएचपीसी के निगम मुख्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए, कमल बहादुर शाह, माननीय मुख्यमंत्री, सुदूरपश्चिम प्रांत ने भारत और नेपाल के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के महत्व का उल्लेख किया, जो सतत विकास और क्षेत्रीय प्रगति के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी साझेदारियां आपसी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अपने संबोधन में आर.के. चौधरी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं नेपाल को, न केवल पड़ोसी के रूप में देखती हैं, बल्कि स्वच्छ और सतत विकास की दिशा में एक कार्यनीतिक साझेदार के रूप में भी देखती हैं। उन्होंने नेपाल सरकार द्वारा 800 मेगावाट पश्चिम सेती और 460 मेगावाट एसआर6 जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू करने के लिए रियायतों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने दौरे के दौरान नेपाली प्रतिनिधि मंडल को नवीकरणीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में एनएचपीसी के विजन, क्षमताओं और योग्यताओं पर प्रस्तुति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री के साथ बीर बहादुर थापा, माननीय मंत्री, भूमि प्रबंधन, कृषि और सहकारिता, घनश्याम चौधरी, प्रांतीय विधानसभा के माननीय सदस्य एवं संसदीय दल के नेता, नरेश शाही, प्रांतीय विधानसभा के माननीय सदस्य, झपट सऊद, प्रांतीय विधानसभा के माननीय सदस्य, डॉ. कमल प्रसाद पोखरेल शर्मा, मुख्य सचिव, सुदूरपश्चिम प्रांत सरकार, शेर बहादुर भंडारी, सदस्य, नीति एवं योजना आयोग, सुदूरपश्चिम, सूरत कुमार बाम, सचिव, भौतिक अवसंरचना मंत्रालय, डॉ. जीतू उपाध्याय, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, राम बहादुर बिस्सा, मुख्यमंत्री के निजी सचिव, मनोज कुमार सिंह, थर्ड सेक्रेटरी, नेपाल दूतावास, नई दिल्ली और विकास कुमार मीना, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर आर.पी. गोयल, निदेशक (वित्त), उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक) और सुप्रकाश अधिकारी, निदेशक (तकनीकी) के साथ एनएचपीसी के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने एनएचपीसी निगम मुख्यालय में स्थापित अत्याधुनिक ह्लअर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूमह्व, 'रियल टाइम जेनरेशन मॉनिटरिंग सेंटर' और 'हाइड्रो एक्सपीरियंस सेंटर' का भी दौरा किया।

सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने तरासा : सुमन सैनी

संवाददाता
लाड़वा

मुख्यमंत्री नायाब सैनी की धर्मपत्नी एवं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी आज लाडवा की निजी होटल मे पहुंची जहाँ उन्होंने लाड़वा विधानसभा के चारों मण्डलों की कार्यकारिणी घोषित की। उन्होंने बताया कि लाड़वा की कार्यकारिणी मुख्यमंत्री नायाब सैनी जी ने स्वयं ही तैयार की है उन्होंने कहा लाडवा से उनका बहुत पुराना रिस्ता है सभी कार्यकर्त्ता उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। सभी लाडवा वासियों का उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनको मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाने मे लाडवा का योगदान है। आज लाड़वा विधानसभा में लाड़वा, बाबैन,गुढ़ा, व पिपली चारों मंडलों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। हरियाणा की प्रथम महिला श्रीमती सुमन सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति में सबको शुबकामनाएं दी गई। लाड़वा से मण्डल अध्यक्ष शिव गुप्ता, गुढ़ा मण्डल से नरेन्द्र सैनी,पिपली मण्डल अध्यक्ष अमरेंदर सिंह व बाबैन से मण्डल अध्यक्ष विकास शर्मा जालखेड़ी ने उपाध्यक्ष सुमन सैनी का बुके देकर स्वागत किया। डॉक्टर गणेश दत्त ने मंच का सफल संचालन करते हुए सुमन सैनी जी का अभिनंदन किया व सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुझे उम्मीद है आप पार्टी को बड़ी ऊँचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रतिनिधि कैलास सैनी, जिला अध्यक्ष तजिंदर सिंह गोल्डी, नगरपालिका चेयरमैन साक्षी खुराना, वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश दत्त, प्रदीप सहगल,सतप्रकाश शर्मा, चारों मण्डलों से लाडवा के अध्यक्ष शिव गुप्ता, गुढ़ा से नरेन्द्र डबखेड़ा, बबैन से विकास शर्मा, पिपली से अमरेंदर सिंह व भाजपा से कार्यकर्त्ता नरेन्द्र सिंघल, सन्नी कालरा, देवेंद्र गोल्डी, नरेश शर्मा, गुरदेव शर्मा, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति संजीव कुमार, पूनम सैनी, मोनिका बंसल सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 242 करोड़ जारी: भारत सरकार द्वारा भी सराहना

संवाददाता
चंडीगढ़

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 31 मार्च, 2025 से पहले 2,22,764 विद्यार्थियों के लिए राज्य के अपने हिस्से के रूप में 242.01 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जारी करके इतिहास रचा है। यह बात पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का राज्य सरकार का हिस्सा शैक्षणिक वर्ष के अंदर ही वितरित किया गया है। इस सक्रिय और विद्यार्थी-केंद्रित पहल की भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना को कुशल, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंजाब सरकार की प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार सामाजिक समानता और सभी के लिए शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर पंजाब सरकार राज्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को एक कुशल, पारदर्शी और विद्यार्थी-अनुकूल तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि वे वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य ने इस प्रमुख योजना के तहत 2,60,000 विद्यार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा था। उल्लेखनीय है कि डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कुल 2,59,685 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,36,575 विद्यार्थियों के आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब सरकार द्वारा प्राप्त सत्यापन की यह सबसे अधिक संख्या है। मंत्री ने आगे बताया कि शेष 13,814 सत्यापित विद्यार्थियों के लिए राज्य का हिस्सा जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ योग्य विद्यार्थी अपने या संस्थानों के स्तर पर आवेदनों को लॉक न करने के कारण वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति का लाभ लेने में असमर्थ थे। इसके मद्देनजर और विद्यार्थियों के कल्याण के हित में पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल को 15 मई, 2025 तक दोबारा खोलने का फैसला किया है, जिससे ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर मिलेगा। डॉ. बलजीत कौर ने राज्य सरकार के इस दृढ़ इरादे को दोहराया कि कोई भी योग्य विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण शैक्षिक सहायता से वंचित न रहे, और विद्यार्थियों और संस्थानों से इस बढ़े हुए अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

गोयल द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का बी.बी.एम.बी. का फैसला सिरे से खारिज

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के जल स्रोत और भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले को सिर से खारिज करते हुए आज कहा कि हरियाणा पहले ही पानी के अपने वार्षिक आवंटन का 104 प्रतिशत उपयोग कर चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब पानी की कमी संबंधी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही पंजाब पानी के अपने हिस्से की रक्षा के लिए वचनबद्ध और दृढ़ है।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने पानी के वितरण संबंधी विवरण पेश करते हुए कहा, ह्लआंकड़ों के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट है कि बी.बी.एम.बी. के अपने रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा पहले ही 3.110 एम.ए.एफ. पानी की खपत कर चुका है जबकि उसका वार्षिक आवंटन 2.987 एम.ए.एफ. है। इसका अर्थ है कि हरियाणा इस वर्ष के लिए अपने हिस्से का 104 प्रतिशत पहले ही उपयोग कर चुका है ह्व उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के किसान पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 153 ब्लॉकों में से 115 ब्लॉक अत्यधिक दोहित वर्ग में हैं, जो 75.16 प्रतिशत बनता है जबकि हरियाणा में केवल 61.53 प्रतिशत दोहित किए गए ब्लॉक हैं।

कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा की मांग पर एक और सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा द्वारा मांगा गया 8500 क्यूसेक पानी उनके पीने के पानी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135 लीटर के मानक आवंटन के आधार पर हरियाणा की करीब 3 करोड़ आबादी के लिए पीने के पानी की जरूरत 1700 क्यूसेक से अधिक नहीं बनती। उन्होंने कहा कि 8500 क्यूसेक की मांग 15 करोड़ के करीब लोगों की आबादी के लिए काफी है। इससे स्पष्ट है कि पानी की यह मांग सिंचाई के उद्देश्यों के लिए की गई है नाकि पीने के पानी के लिए जिसे पंजाब अपने किसानों की कीमत पर साझा करने के सक्षम नहीं है।

कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब में सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पानी की भारी मांग है। पंजाब ने अपने पानी का उपयोग इस तरीके से करने की योजना बनाई थी कि हमारे किसान अप्रैल और मई के महीनों में कपास की फसल उगाने के लिए पानी से वंचित न रहें। हम गेहूं के सीजन के दौरान कम मात्रा में पानी का उपयोग सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि इन महीनों के दौरान कपास की फसल के लिए प्रयुक्त होने वाले इस पानी को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन को बार-बार लिखता रहा है कि साथी राज्यों को पानी का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि वे अप्रैल और मई के महीनों में पीने के पानी सहित अपनी सारी मांगों को अपने हिस्से से पूरा करें। उन्होंने कहा कि हालाँकि पंजाब ने पिछले समय में पानी की कमी के दौरान हरियाणा को सहयोग दिया था लेकिन अब पानी की वर्तमान स्थिति के कारण 4000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ना असंभव है।

श्री गोयल ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार राज्य के जल स्रोतों में से अपने हिस्से की हर बूंद की रक्षा के लिए वचनबद्ध और दृढ़ है और राज्य के आर्थिक एवं कृषि हितों को नुकसान पहुंचाने वाले फैसलों का हमेशा विरोध करती रहेगी।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय के देश के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भाखड़ा डैम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के लिए निभाई जा रही भूमिका पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्री खट्टर को केवल हरियाणा के हक में भुगतने की बजाय पूरे देश के हित का ख्याल रखना चाहिए।

जल स्रोत मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के लिए अपनाई जा रही धक्केशाही वाली नीति भविष्य में संघीय ढांचे के लिए खतरनाक सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें भाखड़ा डैम के पानी की लूट करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले समय में पंजाब ने देश को खाद्य सुरक्षा देने के लिए अपने पानी का अत्यधिक उपयोग किया और भूमि की उपजाऊ शक्ति को देश के लिए खत्म किया।

श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि हम इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अपना हक किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दिया जाएगा।

मोदी सरकार द्वारा पंजाब के अधिकारों पर डकैती निंदनीय; पंजाब का पानी बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी: डॉ. बलजीत कौर

संवाददाता
चंडीगढ़

- पंजाब के पानी, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए पंजाबियों की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी: डॉ. बलजीत कौर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को उसके नदी के पानी के अधिकार से वंचित रखने की कोशिश को कड़ी निंदा करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह कदम लोकतंत्र और संघीय ढांचे की मूल भावनाओं के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि पानी पंजाब की जीवन रेखा है और इस धरती की रीढ़ उसके मेहनती किसानों और मजदूरों की दिन-रात की मेहनत है, जो पूरी तरह से कृषि और पानी पर निर्भर करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के हिस्से का पानी अन्य राज्यों को देने की कोशिश की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है।

उन्होंने कहा, ₹यह कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया हो। मोदी सरकार लगातार पंजाब विरोधी नीति अपना रही है और हमारे राज्य के जायज अधिकारों और भावनाओं की अनदेखी कर रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देते हुए कहा कि पंजाब, जो कि कृषि प्रधान राज्य है, अपनी मिट्टी के पानी में से एक बूंद भी किसी को नहीं दे सकता। पंजाब का किसान और मजदूर हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं और भविष्य में भी किसी भी हालत में यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अन्नदाताओं और मजदूर वर्ग पर सीधा हमला है। ₹हम केंद्र सरकार की इस विश्वासघाती नीति का डटकर विरोध करेंगे और पंजाब के पानी और अधिकारों की लड़ाई हर मंच पर पूरी बहादुरी और जज्बे के साथ लड़ते रहेंगे,₹ उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 1 लाख 30 हजार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कवर किया

पंजाब सरकार श्रमिकों की भलाई की सरकार: तरूण प्रीत सिंह सौंद

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मई दिवस पर सभी श्रमिकों को बधाई दी है। स्थानीय पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने श्रमिकों की भलाई और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई पहलों की शुरूआत की है और कई भलाई योजनाएं चलायी जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा 41 हजार से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 90 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसमें सबसे अधिक 45 करोड़ रुपये निर्माण मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा वजीफा, एक्स-ग्रेशिया के तहत 28 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य बीमा और सर्जरी के लिए 11 करोड़ रुपये और बालड़ी तोहफा स्कीम के तहत 85 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। इसी तरह श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा इस समय के दौरान 6,737 लाभार्थियों को 17.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि लेबर कार्ड और स्कीमों से संबंधित श्रमिकों के लंबित 80 हजार आवेदनों का जनवरी से अप्रैल तक के 4 महीनों में निपटारा कर दिया गया है। पहले यह गिनती 1 लाख 10 हजार थी जो कि अब सिर्फ 30,000 रह गई है।

इससे अतिरिक्त मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 1 लाख 30 हजार निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत प्रति परिवार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। जिसमें दिल की देखभाल, कैंसर का उपचार, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक (हड्डियां) सर्जरी और डायलिसिस एवं गुर्दे की देखभाल शामिल है। सौंद ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 287 करोड़ रुपये लेबर सेस के रूप में इकट्ठा किए गए हैं। चार वर्षों में यह राशि सबसे अधिक है। 2021-22 में 203.94 करोड़ रुपये, 2022-23 में 208.92 करोड़ रुपये और 2023-24 में 180 करोड़ रुपये श्रमिक सेस इकट्ठा किया गया था।

सौंद ने बताया कि श्रमिकों को दी जाने वाली कई भलाई योजनाओं का मौजूदा सरकार के दौरान सरलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब निर्माण श्रमिक भलाई बोर्ड की शगुन स्कीम में पहले पंजीकृत मैरिज सर्टिफिकेट तहसीलदार से लेना अनिवार्य था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह अब केवल धार्मिक संस्थानों जहां शादी की रस्म हुई हो, का सर्टिफिकेट और दोनों परिवारों के माता-पिता द्वारा स्वै-तस्दीक आवेदन आवश्यक है। इस योजना के तहत 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह महिला निर्माण मजदूरों को 21,000 रुपये और पुरुष निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपये प्रसूति लाभ के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाभ लेने के लिए अब केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया गया है। जबकि पहले बालक का आधार कार्ड देना पड़ता था।

- निर्माण और इमारती श्रमिकों की भलाई के लिए पंजाब सरकार द्वारा कई प्रयास
- अब वर्कर निजी अस्पतालों में भी सर्जरियां, ऑपरेशन आदि मुफ्त करवा सकते हैं
- केवल 4 महीनों में 80,000 लेबर और अन्य भलाई स्कीम कार्ड जारी

श्रम मंत्री ने बताया कि लेबर वैल्फेयर बोर्ड में भी विवाह प्रमाणपत्र की शर्त समाप्त कर दी गई है और केवल धार्मिक संस्था जहां विवाह की रस्म हुई हो, का सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ के साथ इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना के तहत 31,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। लेबर वैल्फेयर बोर्ड द्वारा दी जाने वाली प्रसूति योजना का लाभ लेने के लिए पहले बच्चे के जन्म से तीन महीने पहले और तीन महीने बाद के समय में आवेदन करना होता था। लेकिन अब आवेदन करने का समय बच्चे के जन्म के बाद के छह महीने कर दिया गया है।

सौंद ने बताया कि जिन मनरेगा वर्करों ने 90 दिनों से अधिक काम किया है, उन्हें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे बोर्ड के तहत दिये जाने वाले सभी लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा फॉर्म नंबर 27 जो कि श्रमिक द्वारा पंजीकरण के दौरान देना होता है, को और सरल कर दिया गया है ताकि आम श्रमिक भी इसे पंजाबी या हिंदी में भर सके। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली वजीफा स्कीम के लिए भी शर्तें आसान कर दी गई हैं। श्रमिकों के बच्चों को वजीफा प्राप्त करने के लिए पहले किसी भी श्रमिक का कम से कम दो साल से लेबर वैल्फेयर बोर्ड के साथ पंजीकरण होना अनिवार्य था लेकिन अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी श्रमिक जो लेबर वैल्फेयर बोर्ड के साथ पंजीकरण करता है, वह अपने बच्चों के वजीफे के लिए आवेदन कर सकता है और वजीफा प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने भलाई योजनाओं का प्रोसेसिंग समय भी घटा दिया है। पहले सभी योजनाएं एस.डी.एम. की कमेटी और डिप्टी कमिश्नर से मंजूर होती थीं। अब सिर्फ तीन योजनाएं एक्स-ग्रेशिया, बालड़ी और शगुन योजनाओं के अलावा बाकी सभी योजनाओं में एस.डी.एम. कमेटी और डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी हटा दी गई है। पहले मंजूरियों के 9 स्तर थे जो अब सिर्फ 7 रह गए हैं। इससे लाभार्थियों को मिलने वाली राशि 6 महीनों से घटकर सिर्फ एक महीने हो जाएगी।

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब के सभी श्रमिकों से, जो मजदूरी या अन्य निर्माण कार्य करते हैं और जिन्होंने एक साल में 90 दिनों से अधिक काम किया है, अपील की है कि वे खुद को बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ रजिस्ट्र कराएं ताकि वे इसके तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकें। यह पंजीकरण सेवा केंद्र में जाकर या गूगल प्ले स्टोर पर ह्यकिरती सहायक ऐपह्व पर जाकर किया जा सकता है।

उन्होंने पंजाब के सभी उद्योगपतियों से भी अपील की है कि वे अपने वर्करों को लेबर वैल्फेयर बोर्ड के साथ पंजीकरण कराएं और उन्हें मिलने वाली भलाई योजनाओं के लिए आवेदन करवाएं।

पहलगाम एक चुनौती प्रस्तुत करता है: जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं, का किया विमोचन

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि आठ साल में उत्तर प्रदेश की साढ़े बारह लाख करोड़ की इकोनॉमी को लगभग तीस लाख करोड़ तक पहुंचा दिया

फोटोः हि.स.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं का विमोचन करते हुए कहा कि ऐसी पुस्तक लिखना आसान नहीं है। ईमानदारी से लिखना और भी आसान नहीं है। यह पुस्तक प्रेरणादायक सिद्ध होगी। यह बात उन्होंने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहलगाम एक चुनौती प्रस्तुत करता है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनौतियों को स्वीकार किया। आज भारत में हर ओर शिक्षा, सुरक्षा, जल, सड़क और बिजली है। रोजगार है। सबसे खतरनाक चुनौती वो है जो हमें अपने से मिलती है। जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। वह है हमारी सभ्यता। हमारे वेद हैं, भगवद्गीता, रामायण और महाभारत है। कभी भी कर्तव्यपथ से विमुख नहीं होना है। आज देश का बहुमुखी विकास हो रहा है। आर्थिक उन्नति हो रही है। ऐसे मौके पर भारत के समक्ष चुनौतियां आएंगी।

उन्होंने कहा कि चुनौतियों में मुंह नहीं मोड़ना है। लोग कहते हैं कि समय के साथ लोग भूल जाएंगे। लेकिन क्या आपातकाल को लोग भूल गए? कोई भी अपराध हो, कानून के हिसाब से निपटारा होना चाहिए। उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अभिव्यक्ति और वाद-विवाद ही लोकतंत्र है। महत्वपूर्ण पदों पर टिप्पणी करना चिंतनीय है। मैने यह चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि आठ साल में उत्तर प्रदेश की साढ़े बारह लाख करोड़ की इकोनॉमी को लगभग तीस लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। यह शोध का विषय है। मेट्रो के मामले में भी उत्तर प्रदेश अव्वल है। छह शहरों में मेट्रो हैं। चुनौती के प्रति निष्क्रीयता दिखाना, कायरता की निशानी है।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि जब तक हम गांव नहीं पहुंचते, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमें क्या करना है। मेरे पिता जी गांधीवादी थे। उनहोंने गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारा। वह खेती करते थे। मैं भी उनके साथ खेती करती थी। गौपालन किया जाता था। छाछ लोगों में बांट दिया जाता था। आज हम डेयरी से छाछ लेते हैं। इतनी डेरियां हो गयी हैं कि बच्चों के मुंह से दूध-दही छिन गया है। वह समय वापस आना चाहिए। उन्होंने अपने भतीजे के 14 साल की आयु में विवाह के विरोध में पुलिस को बुलाने की घटना के बारे में सुनाया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह हमें रोकना चाहिए। बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विनय जोशी व अन्य ने मिलकर आनंदी बेन पटेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक लिखी है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन में चौदह रत्न निकले, उसी प्रकार इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं। सभी अध्याय एक रत्न हैं। जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वही निखरते हैं। जो भागते हैं वे बिखर जाते हैं। गुजरात के एक छोटे परिवार में जन्म लेकर आज से सात दशक पहले स्कूल जाना और पढ़ना, एक कल्पना थी। मां-बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही भाव आनंदी बेन पटेल को एक शिक्षिका, प्रधानाचार्य, विधान सभा, राज्यसभा के सदस्य, गुजरात सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री और आज देश के सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के रूप में हम सब देख रहे हैं। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह पुस्तक नई पीढ़ी के लिए अपने आप में नई प्रेरणा होगी।

इस मौके पर स्वामी चिदानंद सरस्वती, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एके शर्मा, संजय निषाद, आशीष पटेल समेत अन्य मंत्री, विधायक व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

आत्मबल और परिश्रम से आता है सामाजिक परिवर्तन: आनंदीबेन पटेल

लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक 'चुनौतियां मुझे पसंद हैं' का विमोचन गुरुवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने जीवन संघर्षों की व्यापक चर्चा करते हुए कहा कि यह पुस्तक आत्मबल, परिश्रम और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणादायक गाथा है जो नारी शक्ति, सामाजिक बदलाव और आत्मनिर्भरता का जीवंत दस्तावेज है। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को स्मरणीय बना दिया। उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी स्वयं आयुर्वेदाचार्य हैं और अपने साथ-साथ दूसरों का उपचार भी करती हैं। यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक संत और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ कठिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।

मजदूर भाइयों का सम्मान महत्वपूर्ण है: राज्यपाल

उन्होंने कहा कि पुस्तक के विमोचन के दिन का चयन विशेष रूप से मजदूर दिवस को ध्यान में रखकर किया गया। राज्यपाल ने कहा कि निर्माण कार्यों में लगे मजदूर कम पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वे सटीक डिजाइन को समझकर सड़क, पुल और भवन जैसे भव्य निर्माण करते हैं। उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए यह दिन चुना गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के चरण पूजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ के निर्माण में लगे श्रमिकों के सम्मान का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मजदूर भाइयों का सम्मान महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान में पहली बार आईएसआई प्रमुख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया

एजेंसी (हि.स.)
इस्लामाबाद

फोटोः हि.स.

पाकिस्तान की संघीय सरकार ने मुल्क की प्रमुख खुफिया एजेंसी आईएसआई के मौजूदा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया है। इंटर-सर्विसेज इंटैलिजेंस प्रमुख मोहम्मद मलिक मुल्क के दसवें एनएसए बन गए हैं। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, मंगलवार को कैबिनेट डिवीजन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि जनरल मलिक डीजी आईएसआई के रूप में अपनी भूमिका बरकरार रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। यह नियुक्ति हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच की गई है। एनएसए का पद अप्रैल 2022 से खाली था।

पाकिस्तान में आईएसआई की स्थापना 1948 में भारत के साथ पहले युद्ध के तुरंत बाद सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए की गई थी। सबसे पहले इसका नेतृत्व मेजर जनरल आर. कॉवथॉर्न ने किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आईएसआई पाकिस्तान की सेना का ही हिस्सा है। इसे हर साल हजारों करोड़ रुपये का फंड मिलता है। यह केवल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए 2000 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल करती है। पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह पर्यटकों को मारा है, उसके बाद फिर यह कहा जाने लगा कि यह पूरी आतंकवादी गतिविधि आईएसआई की निगरानी में हुई। इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान की यही कुख्यात एजेंसी है।

भारत को पाकिस्तान की चेतावनी, किसी भी उकसावे की स्थिति में देंगे करारा जवाब

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को भारत को किसी भी दुस्साहस से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी उकसावे की स्थिति में निर्णायक और सशक्त प्रतिक्रिया देगा, हालांकि वह पहले कोई आक्रामक कदम नहीं उठाएगा। डार का यह बयान हाल ही में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। भारत की ओर से इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस्लामाबाद में डार ने आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत की राजनीतिक रूप से प्रेरित और भड़काऊ कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने कहा, आतंकवाद से पीड़ित देश होने के नाते, पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों पर हमले की पीड़ा को बेहतर समझता है।

जातिगत जनगणना से मोदी सरकार करेंगी सामाजिक न्याय के नए युग की शुरूआत : आर के सिंह पटेल

एजेंसी (हि.स.)
चित्रकूट

फोटोः हि.स.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलितों, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है, जिसका देश के दलित, पिछड़े समाज तहेदिल से स्वागत करते हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार ने इस वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया था। यह बातें गुरूवार को बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर के सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले को लेकर कही।

पूर्व सांसद ने कहा कि जातिगत जनगणना सत्ता में रहकर कांग्रेस ने नहीं कराई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार रद्दी की टोकरी में डाल रखा, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। जब भाजपा के समर्थन से जनता दल सरकार बनी तब 1990 में पिछड़ों को आरक्षण मिला। जिसका विरोध भी कांग्रेस ने किया था। सामाजिक न्याय को लागू करने का समय आ गया है। यह दशक समाज के दबे, कुचले, दलित, पिछड़ों की गणना करके उनको अवसर देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर एक अच्छा कदम है।

आर के सिंह पटेल ने मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि देश के 80 फीसदी वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा समाज कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहब आंबेडकर के सपनों को साकार कर रही है। इस निर्णय से सपा, कांग्रेस सहित कई दलों के पीडीए के गुब्बारे की हवा निकल गई है। क्योंकि यह गुब्बारा मात्र दिखावा था, जब उनकी सरकार रही है तो कभी भी इन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं दिए।

सपा ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के आरक्षण को एक जाति के लोगों को देखकर अन्य पिछड़ी जाति के युवाओं के साथ अन्याय किया था। यहां तक लोक सेवा आयोग तक के परिणामों में पिछड़ों के आरक्षण को एक जाति विशेष तक ही सीमित कर दिया गया था। अब भाजपा की सरकार में अन्य पिछड़े वर्ग के सभी जातियों के अभ्यर्थिओं को योग्यता के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के विधयक को लोकसभा में वर्ष 2013 में नाटकीय ढंग से सपा ने अपने दलित सांसद से छिनवा कर लोकसभा के सदन में फाड़ने का कार्य किया था। आज पीडीए का नारा देकर दलितों, पिछड़ों को गुमराह किया जा रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

बांग्लादेश में राजशाही विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार के आवास पर बम से हमला

ढाका। बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रो. इफ्तिखारुल आलम मसूद के आवास के बाहर रात करीब एक बजे बम से हमला किया गया। यह शक्तिशाली देशी बम बताया जा रहा है। विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। प्रो. मसूद राजशाही शहर के बिनोदपुर के मंडलेर मोड़ इलाके में रहते हैं। राजशाही विश्वविद्यालय बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा पुराना विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य परिसर मोतिहार में है। मुख्य परिसर राजशाही शहर के पूर्वी हिस्से में पद्मा नदी के तट से एक मील की दूरी पर है। दे डेली स्टार अखबार ने मोतिहार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अब्दुल मलिक के हवाले से यह खबर दी। पुलिस अधिकारी मलिक ने कहा कि घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद बम की प्रकृति की पुष्टि होगी। अभी तक प्रो. मसूद ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजशाही विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रो. इफ्तिखारुल आलम मसूद ने बम विस्फोट के बाद फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, "मैंने हमेशा फासीवादी ताकतों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। किसी भी खतरे ने मुझे अन्याय का विरोध करने से नहीं रोका, लेकिन अब तक उन्होंने कभी मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं की। कल रात, कायरों ने अंधेरे की आड़ में मेरे घर के गेट पर हमला किया।" विश्वविद्यालय के कुलपति सालेह हसन नकीब ने फेसबुक पोस्ट में हमले की निंदा करते हुए कहा, "यह प्रशासन एक टीम के रूप में काम करता है। एक पर हमला सभी पर हमला है। यह दावा कि देसी बम केवल गेट पर फेंका गया, गलत है। इसने सीधे उनके घर को निशाना बनाया। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने होंगे।" इस बीच, विश्वविद्यालय के छात्रों ने रजिस्ट्रार के आवास पर हमले की निंदा करते हुए आज सुबह 11 बजे विरोध रैली निकाली।

सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडेर, 14.2 किलो वाले रसोई गैस के भाव में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने वीरवार को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को सस्ता कर दिया। हालांकि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस की कीमत तय करने के लिए हर महीने की शुरूआत में होने वाले रिवीजन के बाद कॉमर्शियल गैस की कीमतों में आज 14.50 रुपये से लेकर 17 रुपये प्रति सिलेंडर तक की कमी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। कीमत में की गई कटौती के बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के लिए 1,747.50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि अप्रैल के महीने में इस सिलेंडर के लिए 1,762 रुपये और उसके पहले मार्च के महीने में 1,803 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इस तरह पिछले दो महीने में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 55.50 रुपये की और एक महीने में 14.50 रुपये की कटौती हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में की गई कटौती के बाद अब कोलकाता में इसकी कीमत 1,868.50 रुपये से घट कर 1,851.50 रुपये हो गई है। इसी तरह मुंबई में आज से ये सिलेंडर 1,713.50 रुपये की जगह 1,699 रुपये के भाव पर मिल रहा है। वहीं चेन्नई में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1,921.50 रुपये से कम होकर 1,906 रुपये हो गई है।

पीडीए की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय जातीय जनगणना: अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, इसके लिए सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है। भाजपा सरकार हम लोगों के दबाव पर यह फैसला लेने पर मजबूर हुई है। पीडीए की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। भाजपा सरकार अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही लोगों को न्याय दिलायेगी। संविधान के आगे मन विधान नहीं चल सकता है। मेरा मानना है कि ये इंडिया की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने दूसरे राजनीतिक दलों से आये नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे साथियों का पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके साथ आये हुए लोगों का भी स्वागत करते हैं। पुराने साथी पूर्व मंत्री मूलचंद्र चौहान का भी स्वागत है। जिस समय मैं बिजनौर में प्रदर्शन करने गया था, उस वक्त मूलचंद्र ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। संतोष तिवारी के सपा में आने से गोरखपुर, कुशीनगर बेल्ट मजबूत होगा। मेरठ के साथी और इसी तरह राजा का भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मजदूर दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि श्रमिक दिवस की बधाई देता हूं। आज श्रमिकों की परिभाषा बड़ी हो गयी है। प्रदेश में रोजगार नहीं है। इसलिए चालक एवं डिलवरी ब्वाय भी इस श्रेणी में आये हैं। श्रमिकों की कुछ समस्याएं भी हैं।

श्रमिक वर्ग के प्रति अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं सरकारें: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी श्रमिक भाई-बहनों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी सरकारों को श्रमिकों व कामगार वर्ग के प्रति अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मायावती ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि आज के आधुनिक युग में जब सरकारी स्तर पर भी व्यावसायीकरण चरम पर है। श्रम, श्रमिक व मजदूरों के महत्व को कम आंकने की परम्परा है, किन्तु उस वर्ग का हर स्तर पर शोषण होने के कारण ह्यश्रम दिवसह्न का उद्देश्य व भूमिका आज भी सदैव की भांति प्रासंगिक व आवश्यक है। उन्होंने देश के करोड़ों श्रमिकों व कामगार वर्ग, विशेषकर महिला समाज को ह्यअंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवसह्न की बधाई दी है। कहा कि अपने मानवाधिकारों के लिए निरन्तर संघर्ष करने में उनकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

चार साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड, अप्रैल में कच्चे तेल की कीमत में 16 प्रतिशत की गिरावट

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बनी अनिश्चितता और अमेरिका में मंदी आने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमत पर लगातार दबाव बना हुआ है। इस दबाव के कारण अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साढ़े तीन साल के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत में आई ये सबसे बड़ी मासिक गिरावट है।

कीमत में आई गिरावट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल एक बार फिर 60 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे गिर गया है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4 बजे तक ब्रेंट क्रूड 59.52 डॉलर तक गिर गया था। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड लुढ़क कर 56.58 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया था। क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 4 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड की कीमत में और भी गिरावट आ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की घोषणा करना है। ओपेक प्लस देशों की 5 मई को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने पर औपचारिक फैसला लिया जा सकता है।

ओपेक प्लस देश की अगुवाई कर रहे सऊदी अरब ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए उत्पादन में कटौती करने के पक्ष में नहीं है। इसके विपरीत, वो क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने हिस्सेदारी को मजबूत कर सके।

सऊदी अरब और उसके जैसे ओपेक प्लस देशों का ये रवैया पहले की मार्केट स्ट्रेटजी के पूरी तरह से विपरीत है, जिसमें उत्पादन में कटौती करके क्रूड ऑयल की कीमत को बैलेंस करने की कोशिश की जाती थी। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस के आठ सदस्य देशों ने क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के मुद्दे पर अपनी सहमति दे दी है। अब 5 मई को होने वाली बैठक में इस मुद्दे को औपचारिक फैसले के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

एफपीआई ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ाया निवेश, बाजार में तेजी की संभावना बढ़ी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में फिलहाल उतार-चढ़ाव बना नजर आ रहा है। अप्रैल में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने जोरदार छलांग लगाई। वहीं कुछ मौकों पर दोनों सूचकांकों को बड़ी गिरावट का भी सामना करना पड़ा। इस उतार-चढ़ाव के बाद पिछले एक सप्ताह से शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से छोटे निवेशकों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। दूसरी ओर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने पिछले कुछ दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश किया है। माना जा रहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जिस तरह बुलिश पोजीशन बनाना शुरू किया है, उससे शेयर बाजार आने वाले दिनों में बड़े अपसाइड ब्रेक आउट का बेस बनाता हुआ नजर आ सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले दो सप्ताह के दौरान 97,938 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में आने वाले दिनों में बुलिश मूवमेंट बनने की उम्मीद है।

यूक्रेन को आखिरकार करना पड़ा अमेरिका से खनिज समझौता

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

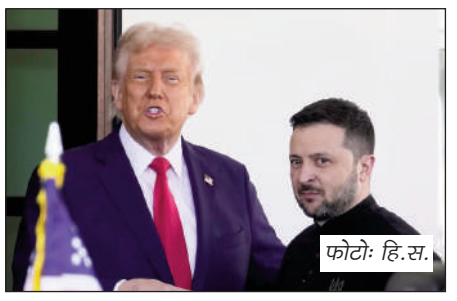
फोटोः हि.स.

रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के अहसानों से दबे यूक्रेन को ना-नुकुर करते हुए आखिरकार खनिज समझौते पर सहमत होना पड़ा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पुष्टि की है कि अमेरिका और यूक्रेन ने खनिज संसाधन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यह समझौता, दोनों देशों के बीच खनिज संसाधन समझौते के समन्वय में अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक निवेश कोष स्थापित करेगा।

एबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, यह समझौता अमेरिका को यूक्रेनी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर अधिकार देता है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने विज्ञप्ति में कहा कि यह समझौता रूस को स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन लंबे समय तक एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन पर केंद्रित शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी लोगों और यूक्रेनी लोगों के बीच इस साझेदारी की कल्पना की। इसके अलावा बेसेंट ने एक्स पोस्ट भी इस समझौते की चर्चा की है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फरवरी के अंत में खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले थे। ओवल ऑफिस में दोनों के बीच तनावपूर्ण बातचीत के बाद यह योजना पटरी से उतर गई थी।

पाकिस्तान ने बालाकोट की सैफुल मलूक झील को पर्यटकों के लिए खोला

एजेंसी (हि.स.)
इस्लामाबाद

फोटोः हि.स.

पाकिस्तान के बालाकोट की काघन घाटी में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सैफुल मलूक झील को छह महीने बंद रहने के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। राजकुमार सैफुल मलूक और परी बदीउल जमाल की रोमांटिक किंवदंती से जुड़ी यह झील प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, पिछले साल नवंबर में भारी बर्फबारी के कारण झील की ओर जाने वाली सड़क बंद कर दी गई थी। अब इसे साफ कर यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। अब पर्यटक एक बार फिर झील के आसपास बर्फ से ढके नजारों का आनंद ले सकेंगे। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा जिले में स्थित है। बालाकोट इस्लामाबाद से लगभग 190 किलोमीटर, जम्मू-कश्मीर के उरी से 81 किलोमीटर और नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर दूर है। पर्यटन सलाहकार जाहिद चानजेब और काघन विकास प्राधिकरण के महानिदेशक शब्बीर खान कहना है कि भारी मशीनरी की मदद से सड़क को साफ कर झील तक जाने का मार्ग बहाल कर दिया गया है। मुल्क के बाकी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप है, मगर यहां का मौसम सुहावना है। झील के खुलने से सैकड़ों स्थानीय जीप चालकों के लिए आजीविका के अवसर मिलने की भी उम्मीद है।

प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट भी की

नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सांप्रदायिक तनाव, बाजार बंद

एजेंसी (हि.स.)
नैनीताल

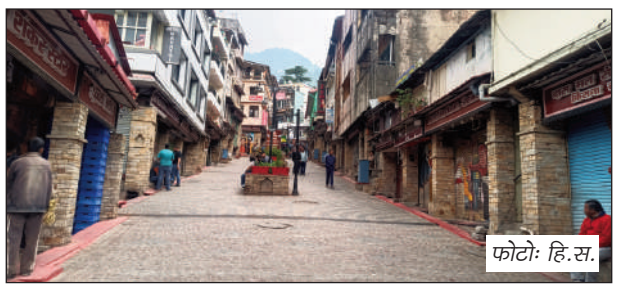
फोटोः हि.स.

जिला मुख्यालय नैनीताल में एक 12 वर्षीय बालिका के साथ दूसरे समुदाय के 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया है। इस घटना के विरोध में बुधवार रात हिंदूवादी संगठनों के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट भी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

बुधवार को हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने इसी घटना को लेकर जुलूस निकाला और कुमाऊं कमिश्नरी पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। घटना के विरोध में आज तल्लीताल और मल्लीताल व्यापार मंडलों के आह्वान पर नगर के सभी बाजार बंद रहे। कुछ विद्यालय भी बंद रहे और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी ठप रहीं। शहर में वाहनों की आवाजाही भी कम रही। शहर में तनाव की स्थिति है, लेकिन पुलिस के नियंत्रण में है। नगर से बड़ी संख्या में सैलानी लौट चुके हैं और नगर की प्रमुख डीएसए कार पार्किंग भी लगभग खाली हो गयी है।

नगर में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी-पुलिस बल मौजूद हैं। समाचार लिखे जाने तक भी हिंदूवादी कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी व विरोध-प्रदर्शन जारी था। रात्रि में आरोपित के पुत्र द्वारा घटना में प्रयुक्त थार को गायब किये जाने के भी आरोप है। बताया जा रहा है कि थार को रात्रि में ही कालाढुंगी से आगे जाते देखा गया है।

नगर कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि मामले में आरोपित 65 वर्षीय उस्मान ठेकेदार के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की बलात्कार से संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसे सुबह ही न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जबकि पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण किया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने बताया कि नगर में तेजी से स्थिति सामान्य हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 वर्षीय पीड़िता अपनी मां एवं 15 वर्षीय बड़ी बहन के साथ नगर के एक क्षेत्र में आरोपित के घर के पास ही रहती है। जबकि आरोपित की स्वयं दो शादियां एवं एक चिकित्सक पुत्र सहित अन्य कई संतानें हैं। इधर आरोपित की मां कहीं बाहर गयी हुई थी और घर में दोनों बहनें थीं। इस दौरान आरोपित बच्ची को कभी 50 तो कभी 200 रुपये तक देकर उससे करीबी रिश्ता बनाता रहा और गत 12 अप्रैल को बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के गैराज में खड़ी लाल रंग की संभवतया थार कार में ले जाकर, बच्ची के शोर मचाने पर कपड़ा ठूंसकर उसने बच्ची से जबरन दुष्कर्म किया। इससे बच्ची लहूलुहान भी हो गयी। आरोपित ने बच्ची को किसी को न बताने को लेकर धमकियां भी दीं। इस कारण बच्ची का

प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई सीएसके, धोनी बोले- कैच छोड़ना पड़ा भारी

18 बॉल में बिखर गई पारी, चहल की हैट्रिक से लगा झटका

एजेंसी (हि.स.)
चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को बुधवार को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही आईपीएल 2025 में वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। मैच के बाद कप्तान एमएस धोनी ने टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि 190 रनों का स्कोर 'थोड़ा कम' था और कुछ जरूरी कैच छोड़ने से उन्हें नुकसान हुआ। धोनी ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि हमने पहली बार एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, लेकिन मुझे लगता है हम थोड़ा पीछे रह गए। बैटिंग यूनिट का प्रयास अच्छा था, लेकिन हमे और रन बनाने चाहिए थे। ब्रेविस और सैम करन की साझेदारी शानदार रही, लेकिन कुछ जरूरी कैच नहीं पकड़ने से विपक्षी टीम

फोटोः हि.स.

को गति मिल गई।'

सीएसके की पारी 19.2 ओवर में 190 रन पर सिमट गई। एक समय टीम 14 ओवर में 126/3 पर थी और 200+ स्कोर की ओर बढ़ रही थी। करन और ब्रेविस की 78 रन की साझेदारी ने रन रेट को बढ़ाया, लेकिन 18वें ओवर में करन (88 रन) के आउट होते ही टीम ने अंतिम 14 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए। 19वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक सहित चार विकेट लिए और चेन्नई ने अंतिम छह विकेट 18 रन में गंवा दिए।

इस सीजन में चेन्नई का बल्लेबाजी प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। टीम का रन रेट (8.23) अब तक का सबसे कम है। रुतुराज गायकवाड़ के कंधे की चोट के चलते बाहर होने के बाद टीम ने शैक राशीद और आयुष म्हात्रे जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और राहुल त्रिपाठी जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी फ्लॉप रहे। धोनी ने करन की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, 'वो हमेशा टीम के लिए योगदान देना चाहता है। इस बार हमें होम ग्राउंड पर अच्छी पिच मिली, जिसका उसने फायदा उठाया। पिछले कुछ मैचों में पिच धीमी थी, जिससे उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज की पिच पर उसे मदद मिली और वह अच्छा खेला। मुझे लगता है हमें 15 रन और बनाने चाहिए थे।'

धीमी ओवर गति के कारण पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर लगा जुमार्ना

नई दिल्ली। चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) पर चार विकेट से मिली रोमांचक जीत के बाद पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के कप्तान श्रेयस अय्यर पर धीमी ओवर गति के चलते 12 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। आईपीएल 2025 में यह पीबीकेएस की पहली ओवर-रेट संबंधी गलती है। धीमी ओवर गति के कारण पंजाब को 19वें ओवर से पहले एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर लाना पड़ा, लेकिन इसका असर युजवेंद्र चहल के प्रदर्शन पर नहीं पड़ा। चहल ने जादुई गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में चार विकेट चटकाए, जिसमें उनकी दूसरी आईपीएल हैट्रिक भी शामिल रही। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने सैम करन के 47 गेंदों में 88 रन की बदौलत 18 ओवर में 177/5 रन बना लिए थे और स्कोर 200 पार जाता दिख रहा था।

चैंपियंस लीग सेमीफाइनलः इंटर मिलान से दो बार पिछड़ने के बाद बार्सिलोना ने 3-3 से की बराबरी

- ओलंपिक स्टेडियम में रोमांचक भिड़ंत, यामाल ने रचा इतिहास, समर का आत्मघाती गोल बना बराबरी का कारण

एजेंसी (हि.स.)
बार्सिलोना

फोटोः हि.स.

चैंपियंस लीग 2024-25 के सेमीफाइनल के पहले चरण में बुधवार को बार्सिलोना और इंटर मिलान के बीच खेले गए मुकाबले में फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। इंटर मिलान जहां दो बार बढ़त लेने में कामयाब रही, वहीं बार्सिलोना ने दोनों बार शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 3-3 की बराबरी पर खत्म किया। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में युवा लमिन यामाल ने एक ऐतिहासिक गोल दागा और दो बार गेंद को बार पर भी मारा।

मैच की शुरूआत ही धमाकेदार रही। इंटर मिलान के मार्कस थुराम ने मुकाबले की शुरूआत के महज 30वें सेकंड में शानदार बैकहील गोल दागते हुए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल इतिहास का सबसे तेज गोल कर डाला। इसके बाद डेंजल डम्फ्रीज ने कॉर्नर से मिले मौके को हवा में छलांग लगाकर गोल में तब्दील किया और इंटर को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी।

हालांकि बार्सिलोना ने हार नहीं मानी। टीम के 16 वर्षीय स्टार यामाल ने अपने 100वें क्लब मैच में शानदार एकल प्रयास से गोल दागा और टीम को वापसी की राह दिखाई। यह गोल उन्हें चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में स्कोर करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बना गया। यामाल ने थुराम को पीछे छोड़ा, मखितारियन को छकाया और फिर बाएं पोस्ट से गेंद को गोल में डाला। पहले हाफ के 38वें मिनट में पेड्री के पास पर रफिन्हा ने हेड से बॉल फॉरवर्ड की और फेरान टोरेस ने पास पर रिएक्ट करते हुए क्लोज रेंज से गोल किया। स्कोर 2-2 हो गया। हालांकि, दूसरे हाफ में डम्फ्रीज ने एक बार फिर हेडर से गेंद डाली, जो ओल्मो से लगकर गोल में चली गई और इंटर को तीसरी बार बढ़त मिली।

इंटर की बढ़त ज्यादा देर नहीं टिक पाई। यामाल के कॉर्नर को रफिन्हा ने बॉक्स के किनारे से ताकतवर शॉट मारा, जो क्रॉसबार से लगकर गोलकीपर सोमर के सिर पर टकराया और गोल में चला गया। यह आत्मघाती गोल स्कोर 3-3 कर गया। मुकाबले के अंतिम मिनटों में यामाल ने फिर एक बेहतरीन शॉट मारा जो क्रॉसबार से टकरा गया। अंततः मुकाबला ड्रॉ रहा। अब इस रोमांचक टाई का दूसरा चरण अगले मंगलवार को मिलान में खेला जाएगा, जहां विजेता 31 मई को म्यूनिख में होने वाले फाइनल में पेरिस सेंट-जर्मेन या आर्सेनल से भिड़ेगा।

लेडी श्रीराम कॉलेज और किरोड़ी मल कॉलेज बने पीएसपीबी बाबा दीप सिंह बास्केटबॉल चैंपियन

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

लेडी श्रीराम कॉलेज और किरोड़ी मल कॉलेज चौथी पीएसपीबी बाबा दीप सिंह बास्केटबॉल प्रतियोगिता में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में चैंपियन बने हैं। महिला वर्ग के फाइनल में लेडी श्रीराम कॉलेज ने रामजस कॉलेज को 49-31 से हराकर यह प्रतियोगिता जीती और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवॉर्ड लेडी श्रीराम कॉलेज की विपासना को मिला। पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में किरोड़ी मल कॉलेज ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को 83 -75 से हराकर यह प्रतियोगिता जीती। कॉलेज के दक्ष चौधरी को मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला।

प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि हॉकी इंडिया की डायरेक्टर रणजीत गिल थीं। उनके साथ गेस्ट ऑफ आनर इंडियन हॉकी प्लेयर हरजीत सिंह, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी गौतम वढेरा और मेजबान खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह थे। इनके साथ खालसा कॉलेज की डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डॉ इंदरप्रीत कौर नंदा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किये।

ग्लेन मैक्सवेल की उंगली में फ्रैक्चर, सीजन लगभग समाप्त

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025)में पंजाब किंग्स के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का सीजन लगभग खत्म हो गया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ टॉस के दौरान पुष्टि की कि मैक्सवेल की उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल टीम ने उनके रिप्लेसमेंट को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। श्रेयस ने कहा, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैक्सवेल की उंगली फ्रैक्चर हो गई है। ईमानदारी से कहूं तो हमने अभी तक रिप्लेसमेंट पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन हमारी टीम का माइंडसेट मजबूत है और हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर से आकर मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर और मैक्सवेल के साथी खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस ने भी पुष्टि की कि मैक्सवेल की चोट गंभीर है। उन्होंने बताया कि यह चोट पिछले मुकाबले से पहले प्रैक्टिस के दौरान लगी थी, लेकिन तब मैक्सवेल ने इसे हल्का समझा। स्टोइनिस ने कहा, उसे लगा था कि चोट हल्की है लेकिन स्कैन के बाद हालात खराब निकले।

मुंबई इंडियंस ने चोटिल विग्नेश पुथुर की जगह रघु शर्मा को टीम में शामिल किया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 सीजन के बीच मुंबई इंडियंस की टीम में एक बदलाव हुआ है। फ्रेंचाइजी ने 32 साल के स्पिन गेंदबाज रघु शर्मा को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें युवा गेंदबाज विग्नेश पुथुर की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो चोटिल होने के चलते शेष सीजन से बाहर हो गए हैं। आईपीएल ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि मुंबई इंडियंस (एमआई) ने लेग स्पिनर रघु शर्मा को विग्नेश पुथुर के स्थान पर अनुबंधित किया है, जो चोट के कारण टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के शेष मैचों से बाहर हो गए हैं। रघु मुंबई इंडियंस के साथ बेस प्राइस 30 लाख रुपये में जुड़े हैं।

11 मार्च 1993 को जालंधर (पंजाब) में जन्मे रघु शर्मा दाएं हाथ के लेग-ब्रेक गेंदबाज हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में पंजाब और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व किया है। 11 प्रथम श्रेणी मैचों में शर्मा ने 19.59 की औसत से 57 विकेट लिए हैं, जिसमें 7/56 का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। लिस्ट ए क्रिकेट में, उन्होंने 9 मैचों में 14 विकेट लिए हैं, जिसमें 4/37 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उन्होंने 3 टी20 मैचों में भी हिस्सा लिया है, जिसमें 3 विकेट लिए हैं।

विग्नेश ने गेंदबाजी से किया प्रभावित- विग्नेश ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ किया था। उन्होंने पहले ही मैच में तीन विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया। विग्नेश ने मौजूदा सीजन में 5 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए। मुंबई की मजबूत वापसी-पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इस सीजन शुरूआती पांच मैचों में केवल एक जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद टीम ने मजबूत वापसी की।

महिला टी20 विश्व कप फाइनल लॉर्ड्स पर

दुबई। महिला टी20 विश्व कप फाइनल अगले साल पांच जुलाई को लार्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला जायेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बारह टीमों का टूर्नामेंट 12 जून को शुरू होगा जिसमें 33 मैच खेले जायेंगे। इसका फाइनल लॉर्ड्स पर होगा जहां 2017 महिला वनडे विश्व कप का फाइनल भी खेला जा चुका है। लार्ड्स के अलावा विश्व कप के मैच ओल्ड ट्रैफर्ड, हेडिंग्ले, एडबस्टन, ओवल, हैंपशर बाउल और ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड पर खेले जायेंगे। टूर्नामेंट में टीमों को दो समूहों में बांटा जायेगा जिसके बाद नॉकआउट खेला जायेगा। आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज समेत आठ टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं जबकि बाकी चार टीमों का चयन आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर 2025 से होगा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, ब्रिटेन में सभी टीमों को अपार समर्थन मिलता है। 2017 में लार्ड्स पर महिला विश्व कप फाइनल में स्टेडियम खचाखच भरा था और फाइनल के लिये इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती।

एशियन चैंपियंस लीग से बाहर हुई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल-नासर

एजेंसी (हि.स.)
जेद्दाह

फोटोः हि.स.

एशियन चैंपियंस लीग एलाइट के सेमीफाइनल में बुधवार देर रात एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जापानी क्लब कावासाकी फ्रंटेल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल-नासर को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। सऊदी प्रो लीग की इस महंगी टीम को उस वक्त झटका लगा जब यूटो ओजेकी और अकीहिरो इएनागा ने गोल दागे। हालांकि सादियो माने और ऐमान याा ने अल-नासर के लिए वापसी की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कतर की अल-सद को क्वार्टरफाइनल में हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी कावासाकी फ्रंटेल ने सेमीफाइनल में भी तेज शुरूआत की। मैच के 10वें मिनट में तत्सुया इटो ने शानदार वॉली के जरिए गोल दागा और कावासाकी को 1-0 की बढ़त दिलाई। 28वें मिनट में सादियो माने ने रोनाल्डो की टीम को बराबरी दिलाई। उनका शॉट जापानी डिफेंडर मारुयामा के कंधे से हल्का डिफ्लेक्ट होकर गोल में गया। इसके बाद रोनाल्डो ने हेडर और ओवरहेड किक से गोल की कोशिशें कीं लेकिन सफलता नहीं मिली। पहले हाफ के खत्म होने से चार मिनट पहले इटो की तेज दौड़ और शॉट पर बेंटो ने बचाव किया लेकिन ओजेकी ने रिबाउंड पर गोल दाग दिया। दूसरे हाफ में अल-नासर ने वापसी की कोशिशें तेज कीं, लेकिन 76वें मिनट में कावासाकी के सब्स्टीट्यूट एरिसन ने शानदार मूव बनाते हुए इएनागा को पास दिया, जिन्होंने तीसरा गोल दागा।

मनोरंजन

मुंबई में 'रामायण' की शूटिंग शुरू, साउथ के यश दिखेंगे रावण की भूमिका में

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' कई दिनों से चर्चा में है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। दोनों कुछ महीनों से फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म में साउथ के सुपरस्टार यश रावण की भूमिका निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। मुंबई के फिल्म सिटी में रावण दरबार लगाया गया है।

फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अब यह आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है कि सुपरस्टार यश इस मेगा प्रोजेक्ट में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। शूटिंग शुरू करने से पहले यश ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। सूत्रों के अनुसार, यश ने मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और वह अगले महीने तक वहीं रहेंगे। इस दौरान फिल्म का एक अहम हिस्सा शूट किया जाएगा। फिल्म सिटी में शूटिंग जोरों पर है, जहां पर रावण की लंका का एक भव्य और भयानक सेट तैयार किया गया है, जो इस पौराणिक गाथा को भव्य रूप देने में मदद करेगा।

यश की रावण के रूप में एंट्री ने 'रामायण' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। फिल्म में सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक शूटिंग शुरू नहीं की है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने किरदार को लेकर कहा था कि यह उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। यह पौराणिक गाथा दो भागों में बनाई जा रही है, जिनमें से पहला भाग 2026 में रिलीज होने की संभावना है। फिल्म में लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अजिंक्य देव, आदिनाथ कोठारे और कई अन्य कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन

केन्द्र सरकार ने हाल ही में पहलगाम हमले के बाद बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भारतीय यूजर्स के लिए बैन कर दिया है। इस कदम से भारत में पाकिस्तानी सितारों के प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। इस बैन में प्रमुख पाकिस्तानी सितारों का नाम शामिल है, जिनमें शाहरुख खान के साथ फिल्म 'रईस' में काम करने वाली अभिनेत्री माहिरा खान से लेकर हानिया आमिर तक के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी शामिल हैं। अब भारत में इन पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाई नहीं दे रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस तनाव के बीच कई पाकिस्तानी कलाकारों पर गाज गिरी है, जिनमें हानिया आमिर, माहिरा खान, अली जफर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज और इमरान अब्बास जैसे नाम शामिल हैं। हानिया आमिर की भारत में भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उन्हें बड़ी संख्या में भारतीय फॉलो करते हैं। इस हमले के बाद हानिया ने भारत के प्रति अपना समर्थन भी जताया था और इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया था। इसके बावजूद भारत सरकार ने इस वक्त इन पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म 'अबीर-गुलाल' की रिलीज पर रोक लगा दी थी। यह फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसमें फवाद के साथ अभिनेत्री वाणी कपूर मुख्य भूमिका में थीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही इस फिल्म को भारत में बैन करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इस फिल्म के जरिए फवाद खान 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। इससे पहले उन्हें आखिरी बार 2016 में करण जौहर की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में देखा गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा भारत में आक्रोश है और आतंकवाद को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान को इसका सबक सिखाने की मांग तेज हो गई है। चाहता है। इस गुस्से का असर पाकिस्तान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा है। भारत सरकार ने पहले ही पाकिस्तान के कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था और अब हाल ही में कुल 16 से ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों को भी भारत में बैन किया गया है, जिससे अब वे भारत में नहीं देखे जा सकते हैं।

औद्योगिक एवं निर्माण श्रमिकों के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर स्टाइलम इंडस्ट्रीज, फेज-1 औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित

संवाददाता
पंचकूला

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, डीएलएसए सुश्री अपर्णा भारद्वाज के मार्गदर्शन में औद्योगिक एवं निर्माण श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) की कार्य योजना के अनुसार आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम श्रम विभाग के सहयोग से स्टाइलम इंडस्ट्रीज, फेज-1 औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों, वित्तीय सहायता योजनाओं और उनके सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के लिए बनाए गए सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करना था।

जागरूकता शिविर में सहायक श्रम आयुक्त सुश्री अंजना गोयल के साथ श्रम निरीक्षक सुश्री किरण वर्मा और श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया। निरीक्षक सुश्री किरण वर्मा ने श्रम कानूनों, मजदूरी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और अन्य राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी पहलों के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की। यह सत्र संवादात्मक था, जिसमें श्रमिक सक्रिय रूप से शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता की मांग की।

कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों, वित्तीय सहायता योजनाओं और उनके सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के लिए बनाए गए सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करना

इस मौके पर अपर्णा भारद्वाज ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने श्रमिकों से किसी भी शोषण या अन्याय की रिपोर्ट करने का आग्रह किया और उन्हें बताया कि जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है। उन्होंने नालसा कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 साझा किया, जो मार्गदर्शन या कानूनी सहायता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। उन्होंने श्रमिकों को कानूनी सेवा प्राधिकरणों से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा, ष्यदि आपको कोई समस्या है, तो आप 15100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अपर्णा भारद्वाज ने उपस्थित लोगों को श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, जिनमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना, दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए शिक्षा सहायता और महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ शामिल हैं।

इसके बाद अपर्णा भारद्वाज ने पंचकूला के सेक्टर-20 में एक निर्माण स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साइट पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की। उन्होंने पुरुष और महिला दोनों ही तरह के श्रमिकों से बात की और उनकी कार्य स्थितियों पर ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के तहत उनके कानूनी संरक्षण और कल्याण अधिकारों के बारे में जागरूक किया। महिला श्रमिकों और उनके बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। श्रीमती अपर्णा भारद्वाज ने उन्हें कार्यस्थल के मुद्दों के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें जब भी जरूरत हो, पूर्ण कानूनी सहायता का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम को श्रमिक समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सत्र के दौरान साझा किए गए संदेशों को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए जागरूकता पुस्तिकाएं और सूचनात्मक सामग्री वितरित की गईं। उन्होने कहा कि यह पहल सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए डीएलएसए पंचकूला की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

मई दिवस पर सीपीयूजे ने बनाई मानव श्रृंखला

चंडीगढ़-पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (सीपीयूजे) के सदस्य गुरुवार को चंडीगढ़ में सेक्टर-17 प्लाजा में मई दिवस रैली में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाते हुए। सिटी दर्पण

संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़-पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (सीपीयूजे) ने मई दिवस के उपलक्ष्य में तथा मजदूर वर्ग के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के बलिदान को याद करने के लिए सेक्टर-17 प्लाजा में रैली का आयोजन किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर मानव श्रृंखला बनाई तथा अपनी वास्तविक मांगों पर जोर दिया। रैली को संबोधित करते हुए सीपीयूजे अध्यक्ष विनोद कोहली ने कार्यरत पत्रकारों के वेतन में संशोधन की मांग की। अंतिम संशोधन 2011 में किया गया था। तब से जीवन-यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर मीडिया काउंसिल करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसके दायरे में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। यूनियन ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की कि अन्य राज्यों की तर्ज पर डेस्क पत्रकारों सहित पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाए। उन्होंने आगे मांग की कि सीटीयू बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा लंबी रूट की बसों में भी बढ़ाई जानी चाहिए। कोहली ने पंजाब सरकार से मांग की कि सभी पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट की सुविधा सहित पंजाब सरकार द्वारा पहले से स्वीकार की गई सभी मांगों को लागू किया जाए।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध

पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ह्यपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टिह्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05, 12, 19 और 26 मई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

संक्षिप्त-समाचार

एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एएसआई के विरुद्ध चालान पेश

चंडीगढ़। एसीबी करनाल द्वारा 30 अप्रैल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार ए.एस.आई. के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय, जीन्द में दिया गया। शिकायतकर्ता ने एसीबी करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके भतीजे सागर व पवन द्वारा मुकदमा संख्या 78 दिनांक 4.3.2025 धारा 115, 190, 191(3), 351(3), 333 बी.एन.एस थाना सदर, जीन्द में दर्ज करवाया है। इस मुकदमा में आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की एवज में अभियोग का तफतीशी अधिकारी स.उ.नि. महेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा उससे 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपए) रिश्वत मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी करनाल द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी ए.एस.आई. महेन्द्र सिंह तफतीशी अधिकारी, थाना सदर, जीन्द को शिकायतकर्ता से 15,000/- रुपये बतौर रिश्वत लेते हुए मौका से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 06 दिनांक 07.03.2025 धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल दर्ज किया गया था।

भाजपा राज में पानी को तरस रही कालका विस की जनता : प्रदीप चौधरी

कालका। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने कालका विधानसभा क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा के कई इलाकों में लोग पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। चौधरी ने कहा कि मोटर खराब होने पर उसे बदलने में 15-15 दिन लग जाते हैं। लोगों की लगातार मांग रही है कि कम से कम 15-20 मोटरें रिजर्व में रखी जाएं ताकि आपात स्थिति में तुरंत बदली जा सकें, लेकिन अधिकारियों और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने पिंजौर के रायपुर गांववासी बुधु का हवाला देते हुए बताया कि गांव में 15 दिन से पानी नहीं आया है। वहीं, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि पहले ही मोरनी में पानी की समस्या को लेकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। कोना गांव के रुलदू राम ने भी पानी किल्लत का जिक्र किया है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि बलोटी गांव में अपना नलकूप तक नहीं है, आज ग्रामीण बता रहे थे कि जंगल का पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बलोटी में नलकूप के लिए जमीन का प्रावधान करे और जल्द समाधान निकाले। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी कालका की जनता बुनियादी सुविधा पानी के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा, ट्रिपल इंजन सरकार की असली सच्चाई इन गांवों में साफ नजर आती है। लोग जंगलों का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और सरकार कागजी दावों में उलझी है।

भगवान परशुराम की तरह माता-पिता सम्मान करें: कुलभूषण गोयल

पंचकूला। पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल ने कहा कि है कि भगवान परशुराम ने हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान किया और उन्हें भगवान के समान ही माना। माता-पिता के हर आदेश का पालन भगवान परशुराम ने किया। हमें भी जीवन में हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान और उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति माता-पिता का सम्मान करते हैं, भगवान भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। कुलभूषण गोयल भगवान परशुराम ब्राह्मण कल्याण संघ हरियाणा और श्री ब्राह्मण सभा रजि. पंचकूला की ओर से दुर्गा माता मंदिर सेक्टर 14 पंचकूला में श्री भगवान परशुराम जन्म उत्सव में बोल रहे थे। भगवान परशुराम ब्राह्मण कल्याण संघ हरियाणा के प्रधान जितेंद्र शर्मा और श्री ब्राह्मण सभा पंचकूला के प्रधान टीआर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने महापौर का स्वागत किया। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह 9 से 10 बजे तक हवन यज्ञ होगा और शाम को 6 बजे ज्योति प्रचंड के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में चिन्मय मिशन पंचकूला की आचार्य ब्रह्मचारिणी कालिंदी चैतन्य द्वारा भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, पंचकूला भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, गौसेवा आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष शर्मा, जिला बार एसोसिएशन पंचकूला के प्रधान राकेश शर्मा, राजस्थान परिवार सेवा संस्थान के प्रधान पवन शर्मा, श्री राधा माधव चैरिटेबल ट्रस्ट पंचकूला के प्रधान राजकुमार शर्मा अति विशिष्ट अतिथि भी पहुंचे। कार्यक्रम में माता मनसा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी शिवकुमार शर्मा, पार्षद जय कौशिक, समाजसेवी सीताराम शर्मा और सत्यवान भारद्वाज विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर भगवान परशुराम ब्राह्मण कल्याण संघ हरियाणा के संरक्षक संजय राय, उपप्रधान हेमंत शर्मा, महासचिव महावीर शर्मा, कोषाध्यक्ष अनिल कौशिक, प्रेस सचिव राजकुमार शर्मा, श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड पंचकूला के मुख्य संरक्षक केडी प्रभाकर संरक्षक, आरएन त्रिखा, महासचिव संजय पंडित, कोषाध्यक्ष एसडी शर्मा प्रेस सचिव, जेएल देवेसर उपस्थित रहे।

उपायुक्त ने पेयजल की शिकायत पर पब्लिक हेल्थ को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

पंचकूला। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में पेयजल पाइपलाइन के गंदे पानी के बीच से आने संबंधी शिकायत पर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व पानी का सैंपल चैक करवाने के निर्देश दिए। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार व वीरवार को जिला में प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता की समस्याओं का मौके पर व जल्द से जल्द समाधान करना हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी स्वयं शिविर से जुडते है व शिविरों में सुनी जा रही समस्याओं की मोनिटरिंग करते है। उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की।